राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष : 32 अंक : 3 जून – जुलाई 2009

1949-2009

ABVP

60 वर्ष पूर्ति
पर विशेष

एक आन्दोलन देश के लिए

Warm Welcome to the Freshers - Delhi

9 July- Students Day Programme - Delhi

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
वर्ष : 32 अंक : 3 ● जून – जुलाई 2009

संरक्षक
अतुल कोठारी

संपादक
डा. मुकेश अग्रवाल

प्रबंध संपादक
नितिन शर्मा

संपादक मंडल
संजीव कुमार सिन्हा
आशीष कुमार 'अंशु'
उमाशंकर मिश्र

फोन : 011 – 23093238 , 27662477
E-mail : chhathrashakti@gmail.com
Website : www.abvp.org

डा. रंजीत ठाकुर द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बी–50, क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, दिल्ली–110007 के लिए प्रकाशित एवं पुष्पक प्रेस, 119, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, ओखला, फेज–1, नई दिल्ली–20 द्वारा मुद्रित

9 जुलाई
छात्र दिवस के अवसर
पर सभी का हार्दिक
अभिनन्दन।

विषय सूची

7 छात्र आन्दोलन के साठ वर्ष

9 सांस्कृतिक मूल्यों की वाहक रचनात्मक युवाशक्ति

17 नशीली समृतियाँ

19 राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक

27 भारत सरकार की 100 दिवसीय शैक्षिक कार्य योजना

मुलाकात

श्री मदनदास – पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री 13

परिचर्चा

क्यों रैगिंग शब्द से छूटती है कंपकंपी 25

परिषद् गतिविधियां 29

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण सम्बन्धित लेखकों के हैं। सम्पादक, प्रकाशक, एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली रहेगा।

संस्कृत वाला गांव मोहद

— आशीष कुमार 'अंशु' —

इन दिनों सुरेन्द्र सिंहजी चौहान अपने गांव को 'संस्कृत ग्राम' बनाने के अभियान पर हैं। वे मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिलान्तर्गत मोहद गांव (करेली मोड़ के निकट) के रहने वाले हैं। नौ साल तक अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक रहे। अब देवभाषा संस्कृत को अपने गांव के घर–घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है।

आप यदि मोहद जाएंगे तो वहां के बच्चे राम–राम, नमस्कार जैसे संबोधनों से आपका अभिवादन नहीं करेंगे। वे आपका अभिवादन नमो:–नम: से करेंगें। अभी यह शुरूआत है, वहां का बच्चा–बच्चा भले ही संस्कृत व्याकरण का पंडित ना हो लेकिन वह संस्कृत में बातचीत करने में सक्षम हैं। गांव के लोगों का स्पष्ट मानना है संस्कृत को व्याकरण के साथ बांध कर रखने से यह आम लोगों की भाषा कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए गांव में इसे संभाषण (बोलचाल) की भाषा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसे आम लोगों से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। गांव में संस्कृत को सुरेन्द्रजी ने ब्राम्हणों की भाषा बनाकर नहीं रखा। गांव का रहने वाला किसी भी वर्ग/समाज का व्यक्ति हो संस्कृत सीख सकता है। वेद पाठ कर सकता है। जिसका परिणाम यह है कि गांव की सेवा बस्तियों में भी बच्चे संस्कृत के वर्गों में भागिदारी करते हैं। संस्कृत संभाषण का अभ्यास करते हैं।

गांव को 'संस्कृत ग्राम' बनाने के अभियान की शुरूआत एक छोटी सी घटना से जुड़ी है। स्वभाव से यायावर सुरेन्द्रजी कर्नाटक के शिमोगा में मथुर नामक गांव देखने पहुंचे। यह गांव जिला मुख्यालय शिमोगा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव में सभी लोग संस्कृत में संभाषण करते हुए मिले। वहीं से संस्कृत सीखन की मन में लालसा पैदा हुई। वृन्दावन जाकर संस्कृत की कार्यशाला में शामिल हुए और पत्राचार से संस्कृत की पढ़ाई पूरी की। अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे सुरेन्द्रजी के अनुसार– ' मैंने सोचा जब इस उम्र में आकर मैं संस्कृत सीख सकता हूं तो फिर बच्चे क्यों नहीं?'

यहीं से मोहद गांव की संस्कृत गांव बनने की शुरूआत हुई। सुरेन्द्रजी ने गांव में संस्कृत की कार्यशाला सन् 1996 में लगाई, जिसमें बच्चों के मार्गदर्शन के लिए हिन्दू सेवा प्रतिष्ठान, बैंगलुरू से सुचिता जी धारे आई। उसके बाद तो एक सिलसिला ही बन गया, शिवराज मिश्र, कृष्ण कुमार पाठक, निधि तिवारी, कुमारी वंदना, प्रियंका दूबे समय–समय पर बच्चों को संस्कृत का अभ्यास कराने आते रहे। प्रत्येक कार्यशाला के बाद गांव के लगभग 150–200 विद्यार्थी संस्कृत जानने वालों श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं। फिर ये बच्चे भी अपने स्तर पर अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों और परिचितों का संस्कृत से परिचय कराके, देवभा ा का विस्तार करने में सहभागी होते हैं। आज मोहद स्थित विद्यालयों में संस्कृत को एक प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है।

गांव के एक संस्कृत छात्र मनिष गुप्ता से पूछा कि जब संस्कृत की हर तरफ उपेक्षा हो रही है ऐसे समय में वह संस्कृत क्यों पढ़ना चाहता है? इसके जवाब में मनिष का जवाब था–

'संस्कृत से मधुरता का विकास होता है, और इससे आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है।' मनिष यह भी कहता है कि संस्कृत सीखने के बाद उसे अपने वेद और दूसरे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए अनुवाद पर निर्भर नही होना पड़ेगा।'

आज अपने संस्कृत प्रेम की वजह से ही पूरे नरसिंहपुर जिले में यह गांव 'संस्कृत बोलने वालों' के गांव के नाम से जाना जाता है। आज मोहद गांव द्वारा की जा रही संस्कृत की यह सेवा वास्तव में काबिले तारीफ है। ■

संपादकीय

छात्र आन्दोलन की विजय यात्रा

9 जुलाई 1949 को जब विद्यार्थी परिषद् की स्थापना हुई तो देश में एक उथल–पुथल का माहौल था। आजादी प्राप्त करने के एक ओर जहां सामाजिक सद्भाव को कायम रखने की चुनौती देश के समक्ष थी वहीं राष्ट्र निर्माण के लिए भी काम करना था। यह वह दौर था जब गांधी जी की हत्या के बाद देश में अस्थिरता का माहौल था। तमाम राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका था। इस बीच राष्ट्रवाद की धारा अविरल बनी रहे और सामाजिक, शैक्षणिक एवं राष्ट्र के उत्थान को लेकर कार्य होते रहें, इसके लिए एक संगठन की जरूरत थी। ऐसे में विद्यार्थी परिषद् की विधिवत स्थापना हुई। आज यह संगठन 60 वर्ष का हो चुका है। अपने गठन से लेकर अब तक देश को बनते बिगड़ते और ऐसे मामलों पर राष्ट्रवादी भूमिका को केन्द्र में रखते हुए विद्यार्थी परिषद् ने कई पड़ाव देखे हैं। आपातकाल दौर भी उन्हीं उतार चढ़ावों में से एक था। जे.पी. आंदोलन में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, परिणामतः सरकार का तख्ता पलट गया। लेकिन इतने पर भी एक अनुशासित संगठन की मिसाल देते हुए अभाविप ने अपने को राजनीति से दूर रखा। यह सिर्फ छात्रों का संगठन नहीं रहा, बल्कि यह तो देश और समाज का संगठन रहा है, देश की सुरक्षा से लेकर, शिक्षा, स्वास्थय, जनजातीय कल्याण, ग्रामीण विकास जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बहुत से लोगों को शायद आडंबरविहीन यह कार्य नजर न आता हो, लेकिन सच यह है कि सामाजिक उत्थान में इन प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

आज जब हम संगठन के 60 साल पूरे कर चुके हैं तो एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है कि हमने इस बीच क्या खोया, क्या पाया, उपलब्धियां क्या रही, खामियां क्या रही और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। इतने लंबे अंतराल के बाद नई परिस्थितियां एवं चुनौतियां देश के सामने हैं। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, शिक्षा का व्यापारीकरण, आर्थिक विषमता, गरीबी, जनस्वास्थ्य, जल संरक्षण, पर्यावरण, नक्सलवाद, बेरोजगारी जैसे दानव मुंह बाये खड़े हैं। आज की परिस्थिति में इन चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त एवं सामयिक रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी। वैसे तो संगठन के विभिन्न स्तरों पर संकल्प, चुनौतियां और विकल्प जैसे विषयों पर विचार विमर्श चल रहा है, साथ ही राष्ट्रीय छात्रशक्ति ने भी विचार मंथन की कड़ी में एक और मनका पिरोने की कोशिश की है। संगठन के अनेक महानुभावों के अनुभव आपको इस अंक में पढ़ने को मिलेंगे और आगामी योजनाओं एवं संकल्प के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा।

किन मुद्दों को लेकर हमें कार्य करने की जरूरत है, संगठन के काम को अधिक सर्वस्पर्शी कैसे बनाया जाये इस पर भी सोचना पड़ेगा। हम दुनिया के सबसे बडे छात्र संगठन हैं इस बात का गर्व होना स्वाभाविक है और संजोना ही नहीं बल्कि निरंतर विस्तार भी करना है। अभाविप के पूर्व संगठन मंत्री मा. मदनदास जी के अनुभवागार से बहुत सी बातें कही हैं, जो इस अंक में आपको पढ़ने को मिलेगा। एनईसी प्रस्ताव की जानकारी, के अलावा विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञानवर्द्धक लेख भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। कैरीयर, कैम्पस गतिविधियां, राज्यों की गतिविधियों के बारे में भी आप जानकारी हासिल कर पायेंगे। फिलहाल देश सूखे के दौर से गुजर रहा है और पहले से ही किसानों की आत्महत्याओं के दंश से अभी देश उबर नहीं पाया है। जबकि सरकारी नीतियां एवं योजनाएं सफेद हाथी साबित हो रही हैं। शिक्षा को व्यापार की वस्तु बना दिया गया है। अब गरीबों बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना एक स्वप्न साबित हो सकता है। महंगाई की मार के चलते जीवन यापन दूभर हो गया है। सरकार है कि अमेरिकापरस्ती में डूबी हुई, खेती के कार्पोरेटाइजेशन की बात हो रही है। देश की 70 फीसदी आबादी जो खेती बाड़ी पर निर्भर है उसे जीवन यापन के कौन से वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराए जायेंगे इसकी बात कहीं नहीं हो रही है, इसके बावजूद इतनी बड़े जनसमुदाय को खेती से बाहर धकेलने की तैयारी चल रही है। यह एक तरह से देश को और अपनी अस्मिता को बेचने के समान है। अभाविप को इन तमाम विषयों को ध्यान में रखकर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है।

प्रा. सबरवाल प्रकरण

असत्य के आधार पर एकतरफा प्रचार अन्यायकारक

उज्जैन के प्रा.सबरवाल की मृत्यु पर सभी को दुःख है, परन्तु उनकी मृत्यु पर उनके पुत्र, कांग्रेस एव अधिकतम मीडिया के लोगों की मिलीभगत से चल रही राजनीती सर्वाधिक दुखद है। लोकतंत्र में टिपणी करने का एवं न्याय के लिए लड़ने का अधिकार सभी को है, परन्तु इस मूलभुत बात का हनन हमारे समाचार माध्यमो द्वारा लगातार हो रहा है। मीडिया का कोई वर्ग अनियंत्रित, झूठा, एकतरफा एव राजनीती से प्रेरित हो जाने पर उसे कैसे संतुलित या नियंत्रित किया जाये यह एक गंभीर चुनौती हमारे लोकतंत्र के सामने खड़ी है। जहा तक अभाविप का सवाल है वह तो प्रकरण के पहले दिन से ही न्यायालयीन प्रक्रिया का सहयोग कर रही है।

झूठे आरोप में परिषद् के तत्कालीन प्रान्त अध्यक्ष को फसाया गया। अगर सरकार निरपेक्ष न होती, तो यह संभव ही नहीं था कि इतने प्रमुख व्यक्ति पर मुकदमा बनता। आरोप के लगते ही परिषद् के सभी 6 कार्यकर्ता स्वयं पुलिस के सामने उपस्थित हुए। इस पुरे मामले में प्रा.सबरवाल के पुत्र श्री हिमांशु सबरवाल तथा उनके पूरे परिवार के द्वारा उठाई गयी आपत्तियों को ध्यान में रखकर माननीय उचतम न्यायालय एव अन्य न्यायालयों द्वारा उन्हें कई प्रकार के विशेष अवसर प्रदान किये गए जिसे विद्यार्थी परिषद् ने हर मोके पर सहर्ष स्वीकार किया। इस प्रकरण को मध्य प्रदेश से हटाकर श्री हिमांशु की मांग पर महाराष्ट्र के नागपुर न्यायालय में स्थानांतरण किया गया।

उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार नागपुर न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गए सरकारी वकील के स्थान पर श्री हिमांशु सबरवाल द्वारा सुझाये गए श्री प्रतुने सदिल्या को सरकारी वकील (विशेष लोक अभियोजक) के तोर पर नियुक्त किया। माननीय न्यायालय ने श्री हिमांशु सबरवाल के आग्रह पर लगभग 20 नए गवाहों को प्रकरण में जोड़ा है। न्यायालय द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की नए सिरे से जांच की प्रक्रिया भी की गयी। जिसके अंतरग ढेर सारे विडियो फुटेज की राष्ट्रीय प्रयोगशाला में जांच की गयी।

यह भी ध्यान रहे की पूरी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सभी 6 आरोपी 36 माह जेल में बंद रहे, एवं जमानत के सामान्य अधिकार से भी वह वंचित रहे।

कई समाचार माध्यमों की सम्पादकीय टिपणी एवं चेनलों में कुछ बाते जिनके आधार पर सारी बाते कही जा रही है वह सरासर झूठ हैं। समाचार माध्यमों में बताया गया कि प्रा. सबरवाल के साथ परिषद् कार्यकर्ताओं की गरम बहस को चेनलों में सभी ने देखा परन्तु सच यह है कि बहस पुलिस प्रभारी प्रा.नाथ के साथ हुई थी। (उसी के सम्बन्ध में अलग से केस भी चल रहा है)

महाविद्यालय में घुसते हुए जो भीड़ चेनलों ने दिखाई वह कांग्रेस प्रेरित आन्दोलनकारियों की थी जो झंडो और हथियारों के साथ एन एस यू आई के समर्थन में महाविद्यालय में घुसे थे जिन्हें पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए बाहर निकाला था। परन्तु चेनलों ने हमेशा इन दो झूठी बातों को प्रचारित किया कि बहस प्रा. सबरवाल के साथ तथा भीड़ परिषद् की थी। जबकि दोनों के वीडियो फुटेज मीडिया के पास उपलब्ध है।

यह बात भी बार–बार कही जाती है की प्रा. सबरवाल को मारते हुए सारी दुनिया ने देखा परन्तु 3 वर्षो से किसी ने भी ऐसी कोई वीडियो फुटेज सामने नहीं लाई, जबकि न्यायालय ने इस हेतु समूची मीडिया को आमंत्रित किया एव पुलिस द्वारा उनके बयान भी लिए गए। इसलिए सच यह है कि दुनिया के सामने जोड़–तोड़ कर बातों को इस तरह प्रस्तुत करते हुए परिषद् को बदनाम करने हेतु इस पूरे प्रकरण में प्रचार को दबावतंत्र के रूप में उपयोग किया गया।

अथार्त हमें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास था वह हमें प्राप्त भी हुआ है ! कुछ प्रश्न अनूतरित रहेंगे कि देश के लिए कार्यरत राष्ट्रवादियों को कब तक ऐसे झूठे प्रचारों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए वर्षो तक जेल में रहना पड़ेगा।

सत्य प्रताड़ित हो सकता है परन्तु पराजित नहीं। ■

छात्र आन्दोलन के साठ वर्ष

– आशुतोष भटनागर –

आजादी का उजाला, कुछ कर गुजरने का हौसला और विश्व की राष्ट्रमालिका में भारत को सम्मानपूर्ण स्थान मिले, इसकी तीव्र आकांक्षा से भरे युवाओं की एक टोली ने साठ वर्ष पहले देखा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का सपना। यह सपना साकार हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में।

9 जुलाई 2009। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के साठ वर्ष। अनवरत् यात्रा का एक पड़ाव। उपलब्धियों का उल्लास। सिंहावलोकन का अवसर। लक्ष्य प्राप्ति के लिये कार्ययोजना बनाने का क्षण।

साठ वर्षों में बहुत कुछ बदला है। विश्व व्यवस्था, अर्थनीति, राजनीति और समाज, सभी में परिवर्तन साफ दिखायी देता है। कुछ बदलाव आवश्यकता के कारण आये हैं तो कुछ मजबूरी बनकर। बदलाव की इस बयार ने जो व्यक्ति अथवा संगठन इन अनावश्यक और अवांछित बदलावों के लिये तैयार नही है, उन्हें किनारे धकेलने की कोशिश की है।

यह बदलाव राष्ट्रीय आकांक्षा को प्रतिबिम्बित नहीं करते। यह बदलाव एक अंतरराष्ट्रीय मुहिम का हिस्सा हैं जो भारत को उसके मूल चरित्र और पहचान से वंचित कर देना चाहते है। इनके समर्थन और विरोध की प्रक्रिया भी लम्बे समय से जारी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना साठ वर्ष पहले इसके विरुद्ध राष्ट्रीय गौरव, स्वाभिमान और आत्मविश्वास के भाव जागरण के एक प्रयास के रूप में हुई थी।

अनुभव आता है कि जिन परिवर्तनों की आस संजोये अभाविप के कार्यकर्ताओं की अनेक पीढ़ियों ने अनामिक भाव से इस राष्ट्रयज्ञ में आहुति दी, वे परिवर्तन आज भी पूरे तौर पर धरातल पर नही उतर सके हैं। शैक्षिक पुनर्रचना पर दशकों से जारी विमर्श आज भी प्रतिवेदनों और प्रस्तावों तक ही सीमित है, ठोस आकार नहीं ले सका। स्थापना के साथ ही परिषद ने जो पहला कार्यक्रम हाथ में लिया, वह था भारतीयकरण उद्योग। देश का नाम भारत हो, हिन्दी देष की राष्ट्र भाषा हो तथा वन्दे मातरम् को राष्ट्र गीत घोषित किया जाय, इन मांगों को लेकर देश भर में जनमत संग्रह कर पचपन लाख से अधिक हस्ताक्षर राष्ट्रपति महोदय को सौंपे।

भारतीयकरण उद्योग की उत्तर प्रदेश की समिति के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे, किन्तु वे मांगे आज भी जस की तस हैं। स्वायत्त शिक्षा पीठ की मांग करने वाले अभाविप के पूर्व महामंत्री डॉ मुरली मनोहर जोशी स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्री बनने पर भी पीठ के गठन में असफल रहे।

शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम आज भी उपनिवेशी दासता का बोझ ढो रहे हैं। वे न संस्कार दे पा रहे हैं और न रोजगार। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद कई दिन तक असफल या कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या के समाचारों से अखबार भरे होते हैं।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध और लोकतंत्र की रक्षा के लिये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में खड़े हुए यशस्वी छात्र आन्दोलन से उपजा राजनैतिक नेतृत्व देश का विश्वास बनाये रखने में सफल नहीं हुआ। जिन कार्यकर्ताओं ने आपातकाल के बाद अपने आप को छात्रसंघ चुनावों से दूर रखने का निर्णय करते हुए चलो गांव की ओर का नारा दिया, उनमें से अधिकांश आज एक राजनैतिक दल के सदस्य के रूप में देखे जा सकते हैं।

इन स्थितियों से जन्म लेते हैं ऐसे अनेक सवाल जिनके उत्तर की अपेक्षा परिषद से बार–बार की जाती है। अनेक बार यह भी साबित करने की कोशिश की जाती है कि अभाविप इन प्रश्नों के उत्तर देती नहीं है, दे नहीं पाती है अथवा देना नहीं चाहती है। निस्संदेह प्रश्न बड़े है, महत्वपूर्ण हैं। एक जिम्मेदार संगठन को ऐसे सभी सवालों के संतोषजनक उत्तर देने भी होंगे। लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि हर उत्तर बयान, सफाई या प्रतिक्रिया के रूप में ही आये। परिषद ने इन प्रश्नों का उत्तर अपने आचरण से दिया है।

पूर्वाग्रह मुक्त विवेचना करने पर उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर पाना सहज है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मूल्यांकन उसके दर्शन और कार्य पद्धति को समझ कर ही किया जा सकता है।

सबसे पहले समझना होगा कि परिषद न तो विद्यार्थियों के बीच काम करने वाली ट्रेड यूनियन है और न ही किसी राजनैतिक दल का भर्ती केन्द्र। वर्षों तक केवल राजनैतिक उद्देश्यों के लिये महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अड्डा जमाने वाले पेशेवर छात्र नेताओं से परिसरों को मुक्त कराने की मांग परिषद लगातार करती रही है। यद्यपि परिषद छात्रों की समस्याओं के हल के लिये भरपूर प्रयास करती है लेकिन यही उसके कार्य का अंतिम बिन्दु नहीं है। शैक्षिक समस्याओं के हल के पीछे स्पष्ट सोच है कि परिसरों से ऐसे योग्य और प्रतिभाशाली विद्यार्थी निकलें जो देश के विकास में अपनी भूमिका निभायें।

महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के परिसर वे स्थान हैं जहां भारत का भविष्य गढ़ा जाता है। इसलिये परिषद ने इन्हें अपना कार्यक्षेत्र बनाया है। जीवंत और स्पंदनयुक्त परिसरों में विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रवाद, सामाजिक समरसता, सर्वपंथ समादर, अंतरराष्ट्रीय बंधुत्व और समर्थ भारत के निर्माण का संकल्प तथा रचनात्मक दृष्टिकोण के विकास का उद्देश्य लेकर परिषद वर्ष भर सक्रिय रहती है।

निरंतर प्रवाहमान जनसंख्या वाले इन परिसरों में संगठन का कार्य अबाधित रूप से चलता रहे, यह स्थायी चुनौती है। परिषद ने बखूबी इसे करके दिखाया है । बढ़ती सदस्यता व इकाइयों की संख्या इसका प्रमाण है। विद्यार्थी काल में अभाविप से जुड़े रहने वाले सैकड़ों–हजारों कार्यकर्ता आज समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह परिषद की विशिष्ट कार्यपद्धति का परिणाम है जिसका मूलमंत्र है व्यक्ति निर्माण के माध्यम से समाज परिवर्तन और अंततः राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महत्कार्य में उनकी प्रतिभा तथा योग्यता का नियोजन।

शिक्षा, कला, साहित्य, विज्ञान, रंगमंच, गैर सरकारी संगठन, पत्रकारिता, योग, अध्यात्म आदि समाज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर परिषद से जुड़े रहे कार्यकर्ता न पहुंचे हों। इतना ही नहीं, वहां उन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और संबंधित क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभायी है। किन्तु राजनीति के प्रभुत्व और मीडिया की भूमिका के कारण प्रायः परिषद से जुड़े रहे और वर्तमान में राजनैतिक दलों में सक्रिय लोगों की चर्चा ही अधिक सामने आती है।

यह सत्य है कि राजनैतिक क्षेत्र में परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं संख्या बहुत अधिक है। वे कार्यकर्ता राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्रवादी स्वरों को मुखर कर रहे हैं, परिषद के लिये यह संतोष की बात है । किन्तु यहां यह रेखांकित करना आवश्यक है कि राजनीति में सक्रिय इन निकटतम लोगों की उपस्थिति, यहां तक कि राज्यों और केन्द्र में उनके सत्तारूढ़ होने की स्थिति में भी परिषद ने दल व सत्ता की राजनीति से ऊपर रहने की स्वयंस्वीकृत नीति का कभी उल्लंघन नहीं किया। सत्ता के अविवेकी निर्णयों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। अपनी नीतियों व सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।

यह भी सच है कि देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के उपरान्त भी हमारे अनेक मुद्दे परिणाम तक न पहुंचे। किन्तु एक छात्र संगठन के लिये यह कोई कम उपलब्धि नहीं है कि वह अपनी प्रवाहमान सदस्य संख्या को दशकों तक अपने आग्रह के बिन्दुओं से न केवल जोड़े रखे अपितु उन्हें आंदोलनरत रखे। भारत परमाणु बम और 18 वर्ष पर मताधिकार जैसे विषयों पर परिषद ने दो दशकों तक बहस चलायी और मुद्दों को जीवित रखा। आज भी अनेक ऐसे अपूर्ण विषय हैं जिन पर परिषद ईमानदार प्रयास जारी हैं।

शिक्षा में व्यापक बदलाव, व्यवस्था की जड़ता पर प्रहार, बाजारवाद के आक्रमण का उत्तर, भारतीय संस्कृति पर हो रहे आघातों का प्रत्युत्तर, घुसपैठ, असुरक्षित सीमाएं, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अन्याय और अस्पृश्यता जैसी अनेक चुनौतियां आज देश के सामने अपने भयंकरतम रूप में खड़ी हैं। इन चुनौतियों को स्वीकार करने की सामर्थ्य देश के छात्र–युवाओं में है, किन्तु उन्हें इसके लिये संकल्पबद्ध करने का काम दल और सत्ता के पिछलग्गू संगठन नहीं कर सकते।

परिषद के लिये यह चुनौतियां एक अवसर हैं जो उसकी भूमिका सुनिश्चित करती हैं और उसके कृतित्व को सार्थकता प्रदान करती हैं। षष्ठिपूर्ति के अवसर पर परिषद अपने तात्कालिक और दूरगामी लक्ष्यों हेतु योजना–रचना करेगी। साठ वर्ष पहले लिया गया संकल्प अवश्य पूरा होगा। यह बात हमें भली भांति स्मरण है कि देश अपनी सभी समस्याओं और चुनौतियों के लिये देश की छात्र–शक्ति की ओर निहारता है। छात्र–शक्ति के प्रतिनिधि संगठन के रूप में छात्र–युवाओं और दूसरे अर्थ में देश को सक्षम नेतृत्व प्रदान करने में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सार्थकता है। ■

सांस्कृतिक मूल्यों की वाहक रचनात्मक युवाशक्ति

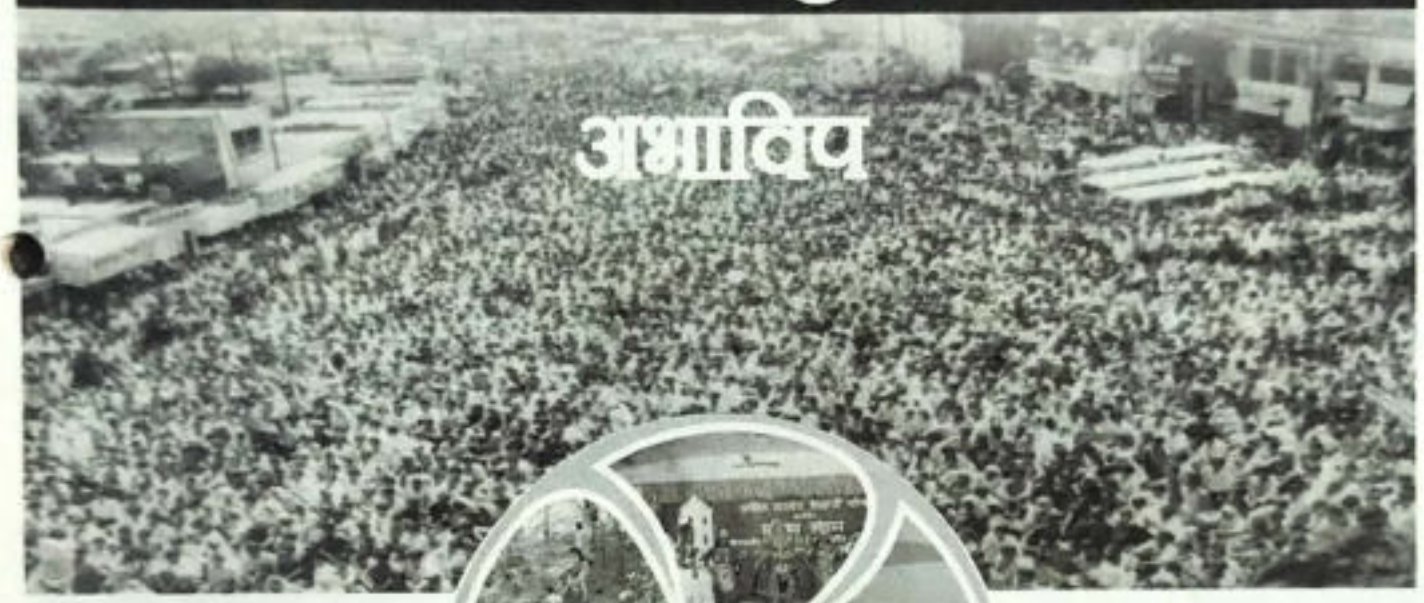

ज्ञान, शील, एकता परिषद् की विशेषता। युवाओं के बीच यह नारा गुंजाने वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (अभाविप) ने युवाओं में रचनात्मक व राष्ट्रवादी सोच विकसित करने का जो संकल्प लिया उसने आज देश की युवाशक्ति का चित्र ही बदल दिया है और परिषद् देखते ही देखते राष्ट्रभक्त, समाजसेवी और संस्कारित युवाशक्ति का प्रतीक बन गई। 9 जुलाई, 1949 को दिल्ली में पंजीकृत यह छात्र संगठन प्रारंभ से ही युवा शक्ति के राष्ट्रवादी स्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। इसलिए इस विचारधारा के लोग इसे एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन कहते हैं। अपने विरोधियों के अंध–विरोध के बावजूद अभाविप आज विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या लगभग 17 लाख है। लगभग 250 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की देखरेख में करीब 4 हजार महाविद्यालयों में इसकी इकाइयां हैं। 9 जुलाई, 2009 को अपनी स्थापना के 60वें वर्ष में प्रवेश करने वाली अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिलिन्द मराठे का कहना है कि इस वर्ष हम लोग अपने सदस्यों की संख्या 20 लाख से अधिक करेंगे। श्री मराठे ने अभाविप की कार्यशैली को इन शब्दों में बताया, अभाविप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और रचनात्मक भाव से संस्कारित छात्र शक्ति के निर्माण में गत 60 साल से लगी है।

– अरुण कुमार सिंह –

अभाविप की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, इस सन्दर्भ में श्री मराठे कहते हैं, '1947 में भारत को आजादी मिली थी। उस समय यह विचार चल रहा था कि देश में सुराज कैसे लाया जाए। कुछ लोगों का कहना था कि आजादी मिलने से हमारा काम हो गया। अब हम आराम करेंगे। कुछ का कहना था कि यह स्वतंत्रता हमारे लोगों ने खून बहाकर प्राप्त की है, इसलिए स्वाधीनता का लाभ हमें मिलना चाहिए। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से सक्रिय राजनीति में आ गए। जबकि एक बड़े समुदाय का मानना था कि स्वाधीनता पहला पड़ाव है। इसको सुराज में बदलने के लिए लगातार किसी को काम करना पड़ेगा। और यह काम भारत की प्राचीन विरासत को ध्यान में रखकर छात्रों के मन में भारत–भक्ति की भावना जगाकर करना पड़ेगा, क्योंकि आज का छात्र ही आगे देश के सभी क्षेत्रों में जाएगा। ऐसा विचार रखने वालों ने विद्यार्थी परिषद् का गठन किया।

अभाविप ने अपने तीन सूत्रों (ज्ञान, शील और एकता) पर आधारित सेवा, संस्कार तथा संघर्ष के मुद्दों पर अपनी गतिविधियां चलाई हैं।

अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील अम्बेकर कहते हैं, "देश में अनेक छात्र संगठन हैं। परन्तु अभाविप और अन्य छात्र संगठनों में अन्तर यह है कि दूसरे संगठन सिर्फ चुनाव के लिए सक्रिय रहते हैं, तो अभाविप रचनात्मक कार्यों के आधार पर छात्रों के बीच अपनी जगह बनाती है। यही कारण है कि अभाविप की इकाइयां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हैं और पूरे देश में अन्य छात्र संगठनों के मुकाबले अभाविप ही डटी रहती है।"

छात्रों एवं देश की विभिन्न समस्याओं के साथ-साथ अभाविप आपदा के समय भी कार्य करती है। लातूर और गुजरात में आए भूकम्प के समय परिषद् के कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों की सहायता के लिए दिन-रात एक किया था। सन् 2004 में आई सुनामी लहर और 2008 में आई बिहार की विनाशकारी बाढ़ के समय अभाविप के कार्यकर्ताओं ने कई राहत शिविर लगाए, जिनकी प्रशंसा स्थानीय प्रशासन ने भी की। अभाविप के कार्यकर्ता अनेक स्थानों पर संस्कार केन्द्र, वाचनालय, रक्तदाता सूची, बुक बैंक, चिकित्सा शिविर, रोजगार प्रशिक्षण एवं निशुल्क कोचिंग जैसे प्रकल्प भी चलाते हैं।

विद्यार्थी परिषद् साल में तीन बड़े कार्यक्रम भी करती है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानन्द की जयन्ती, 9 जुलाई को परिषद् स्थापना दिवस और 6 दिसम्बर को डा. अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर समता दिवस मनाती है। 1966 से अभाविप अन्तर-राज्य छात्र जीवन दर्शन नाम से एक अभियान भी चलाती है। इसके अन्तर्गत एक साल पूर्वोत्तर भारत के छात्रों को शेष भारत का भ्रमण कराया जाता है, तो दूसरे साल शेष भारत के छात्रों को पूर्वोत्तर के सातों राज्यों में घुमाया जाता है। इस तरह लगभग 150 छात्र प्रतिवर्ष एक-दूसरे की संस्कृति, रहन-सहन से परिचित होते हैं। इसका लाभ यह हो रहा है कि ये छात्र एक-दूसरे से भावनात्मक स्तर पर जुड़ रहे हैं और राष्ट्रीय एकता मजबूत हो रही है।

अभाविप ने सामाजिक समरसता के लिए भी अनेक आन्दोलन किए हैं। शिक्षण परिसरों को जातीय राजनीति से बचाने और समाजिक बुराइयों में सुधार के लिए 1982-83 में वीर सावरकर जन्मशताब्दी के अवसर पर समता ज्योति यात्रा निकाली गई। 1988 में जहानाबाद में समरसता यात्रा भी हुई। समाज में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को भी अभाविप सम्मानित करती है। 1991 से अभाविप प्राध्यापक यशवंत राव केलकर के नाम से प्रतिवर्ष किसी एक सामाजिक युवा कार्यकर्ता को 'युवा पुरस्कार' देती है।

बेशक अभाविप का पंजीकरण 7 जुलाई, 1949 को हुआ हो, पर इसकी गतिविधियां 1948 से ही शुरू हो गई थीं। देश की तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक श्रीगुरुजी ने कुछ कार्यकर्ताओं को संस्कारित छात्र शक्ति तैयार करने के लिए एक संगठन की स्थापना करने की सलाह दी थी। इसके बाद 13 जून, 1948 को अम्बाला (हरियाणा) में अभाविप का गठन हुआ और वहीं इसका प्रथम सम्मेलन भी हुआ। इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभाला वरिष्ठ प्राध्यापक श्री ओमप्रकाश बहल ने। सदस्यों में श्री दत्ता जी डिडोलकर, श्री हरवंश राय और श्री दत्तोपंत ठेंगडी शामिल थे।

अभाविप एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है, जिसका लिखित संविधान है। इस संविधान के लेखक थे श्री एकनाथ जी रानडे। अभाविप का प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और हर साल नई कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी 26 प्रान्तों की इकाइयों के अध्यक्ष, मंत्री, संगठन मंत्री के अलावा कुछ अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता भी होते हैं। अभाविप की सदस्यता के लिए छात्रों को वार्षिक 2 रु. और अन्य कार्यकर्ताओं को वार्षिक 10 रु. शुल्क देना पड़ता है। ■

(साभार : पांचजन्य)

अभाविप की गतिविधियां

9 जुलाई, 1949 को दिल्ली में अपनी स्थापना के बाद ही अभाविप ने संविधान सभा को एक मांग पत्र सौंपा। इसमें तीन मुख्य मांगें थीं– 1. देश का नाम भारत हो 2. राष्ट्रभाषा हिन्दी हो 3. राष्ट्रगान वन्देमातरम् हो।

27 सितम्बर 1970– दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय प्रदर्शन। तीस प्रमुख मांगें थीं– भारत परमाणु बम बनाये, 18 वर्ष के युवा को मताधिकार मिले एवं विश्वविद्यालय प्रशासन में छात्रों का सहभाग हो।

6 मार्च, 1979 को दिल्ली में शैक्षिक मांगों को लेकर 10 हजार छात्रों का प्रदर्शन।

आपातकाल का विरोध– गुजरात और बिहार में छात्रों के आन्दोलन को प्रारंभ करने में विद्यार्थी परिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कारण वहां सत्ता परिवर्तन हुआ, जो बाद में आपातकाल के विरोध व लोकतंत्र की रक्षा के लिए जे. पी. आन्दोलन बना, जिसमें परिषद् का व्यापक सहभाग रहा। लोकसंघर्ष समिति के तत्वावधान में 10 हजार छात्रों ने सत्याग्रह किया। 650 कार्यकर्ता मीसा के अन्तर्गत व 4500 कार्यकर्ताओं की विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत गिरफ्तारी।

1978 में छात्रों को ग्राम विकास के विभिन्न कार्यों में सहभागी करने के लिए 'ग्रामोत्थान हेतु छात्र' नाम से एक अभियान चलाया गया। 350 गांवों में प्रभावी कार्य हुआ।

1980 में लोकतंत्र में लोक को जागरूक करने का देशव्यापी अभियान चला।

असम में बढ़ते बंगलादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध परिषद् ने 'असम बचाओ, देश बचाओ' का नारा दिया। राजघाट, दिल्ली से गुवाहाटी तक असम ज्योति यात्रा निकाली गई। 2 अक्तूबर, 1983 को गुवाहाटी में ऐतिहासिक सत्याग्रह हुआ।

जून 1982 में परिषद् ने पश्चिम बंगाल में तीन बीघा गलियारा, बंगलादेश को हस्तान्तरण के विरोध में सत्याग्रह किया।

नक्सल समस्या के विरुद्ध भी अभाविप के कार्यकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश में संघर्ष किया। इसमें 25 कार्यकर्ता शहीद हुए। 1990 में कश्मीर में आतंकवाद के विरोध में देशव्यापी अभियान चलाया गया।

विद्यार्थी परिषद् ने नारा दिया–

'जहां हुआ तिरंगे का अपमान,
वहीं करेंगे उसका सम्मान।'

11 सितम्बर, 1990 को जम्मू में लगभग 10 हजार विद्यार्थियों ने विराट प्रदर्शन किया।

1992 में शैक्षिक अराजकता और शिक्षण संस्थानों के परिसरों में सुधार हेतु आन्दोलन किया गया।

स्वर्ण जयंती वर्ष (1998–99) रू परिषद् ने अपनी स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया। इसके अन्तर्गत पूरे देश में 1.5 लाख वृक्ष लगाए गए। मुम्बई में 12 हजार छात्रों की उपस्थिति में राष्ट्रीय अधिवेशन सम्पन्न हुआ।

26 नवम्बर 2002 को दिल्ली में शिक्षा रोजगार रैली आयोजित हुई। इसमें देशभर से लगभग 75 हजार विद्यार्थी शामिल हुए।

17 दिसम्बर, 2008 को किशनगंज (बिहार) में बंगलादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध विशाल रैली एवं सभा आयोजित हुई। देश के कोने–कोने से अपने खर्चे पर इसमें 40 हजार छात्र–छात्रओं ने भाग लिया। इससे पूर्व पूरे देश में घुसपैठ विरोधी आन्दोलन चलाया गया। इसके अन्तर्गत 915 स्थानों पर घुसपैठ विरोधी सप्ताह, 653 स्थानों पर संकल्प दिवस मनाया गया। 139 जिलों में रैलियां एवं प्रदर्शन हुए। 8241 महाविद्यालय और 15,694 इंटर कालेज बन्द कराए गए। कोलकाता स्थित बंगलादेशी दूतावास के सामने प्रदर्शन हुआ, घुसपैठ विरोधी जागरण यात्रा निकाली गई और देशभर में राष्ट्रीय संगोष्ठियां हुईं। ■

एक आन्दोलन देश के लिए

अभाविप 60 वर्ष पूर्ति योजना

"एक आन्दोलन देश के लिए"

विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस वर्ष अपने 60 वर्ष पूर्ण कर रहा है। किसी भी संगठन के लिए अपनी उपलब्धियों पर चिन्तन के साथ आगे की चुनौतियों के लिए विचार करने का यह अवसर होता है। विद्यार्थी परिषद में चिन्तन, मनन, समीक्षा–योजना यह कार्यपद्धति का भाग होने से होता ही रहता है, परन्तु इन 60 वर्षों के पूर्ण होने के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष योजना बनाई गई है।

इस वर्ष की योजना में अपनी उपलब्धियों व विचारों का व्यापक प्रचार, संगठन का कार्य विस्तार, समाज के प्रभावी व्यक्तियों से संवाद व छात्र–शिक्षकों के साथ व्यापक सम्पर्क का आग्रह है। इस अभियान का स्वरूप समारोह व कार्यक्रमात्मक न होकर व्यक्तिशः प्रयास अधिक है।

- 9 जुलाई विद्यार्थी दिवस के कार्यक्रम देश भर की सभी ईकाईयों पर हो जिनमें छात्रों की अधिकतम सहभागिता हो।
- संगठन के कार्य विस्तार के लिए देश भर में गतवर्ष की सदस्यता 16 लाख से बढाकर इस वर्ष 20 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए सभी प्रान्तों व ईकाईयों में सर्वव्यापी स्वस्पर्शी सदस्यता हो।
- षष्ठीपूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में प्रान्त स्तर पर प्रान्त केन्द्र में एक सार्वजनिक समारोह का कार्यक्रम करना है जिसमें अपना विचार व उपलब्धियाँ समाज के सामने रखी जाये।
- अपने कार्य की आवश्यकता व समाज के अपेक्षा के अनुरूप कार्य में भौगोलिक दृष्टि से व विभिन्न आयामों के कार्य विस्तार के लिए साधनों की आवश्यकता रहती है। इसलिए इस अवसर पर छात्रों व समाज से व्यापक धन संग्रह हो।
- सम्पर्क अभियान इस वर्ष का प्रमुख आग्रह है, सामान्य छात्र, प्राध्यापक, शिक्षाविद समाज के प्रभावी व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क हो। जिला स्तर पर छात्र व शिक्षक प्रान्त व केन्द्रीय स्तर पर समाज के प्रभावी लोगों से मिला जाये। सम्पर्क के साथ परिषद साहित्य भी उन्हें दिया जाये।
- इस वर्ष परिषद कार्य के लिए कार्यकर्ता वर्ष, छः माह के लिए विस्तारक के रूप में कार्य करें यह आग्रह तो है ही लेकिन अधिक से अधिक कार्यकर्ता सम्पर्क अभियान के समय 10 दिन के लिए विस्तारक निकलें।
- वर्ष भर चलने वाले इस अभियान में पर्याप्त साहित्य का प्रकाशन हो :– परिषद के 60 वर्ष पर प्रदर्शनी, सी.डी., फोल्डर के साथ परिषद की उपलब्धियाँ, विद्यार्थी परिषद का परिचय, विद्यार्थी परिषद समाज की आवश्यकता जैसे विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन हो।
- 60 वर्ष पूर्व की योजना के इन विशेष आग्रहों के साथ अपने कार्य विस्तार, कार्य दृढ़ीकरण, शिक्षा क्षेत्र व आयामों पर विशेष प्रयास हमारा इस वर्ष भी रहेगा। ■

मुलाकात

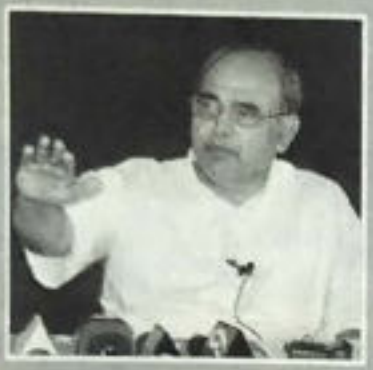

श्री मदन दास

(पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री)

मा. मदन दास जी अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे हैं, बाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में सह सर कार्यवाह के दायित्व पर रहे और वर्तमान में अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनके विस्तृत अनुभवों को बातचीत से साझा कर रहे हैं छात्रशक्ति प्रतिनिधी उमाशंकर मिश्र

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् में आप संगठन मंत्री कब से कब तक रहे?

विश्व हिन्दू परिषद् के मा. गिरीराज किशोर जी अभाविप के प्रथम पूर्णकालिक थे। 1966 से 1970 तक वे अभाविप के संगठन मंत्री रहे। 1970 के त्रिवेन्द्रम अधिवेशन में मुझे दायित्व संभालने का अवसर मिला। 1991 में दत्ता जी सह संगठन मंत्री बने और 92 में मैने उन्हें संगठन मंत्री का भार सौप दिया।

अभाविप जैसे छात्र संगठन की जरूरत क्यों पड़ी?

छात्र तो पूरे देश में हैं इसलिए उनमें जो गुण उत्पन्न करना है, रचनात्मकता है, राष्ट्रभक्ति है, शिक्षा के बारे में उनकी जो दृष्टि है, शिक्षा के परिवर्तन में छात्रों के महत्व की भूमिका, समाज के परिवर्तन में छात्रों की भूमिका, छात्र आज का नागरिक है कल का नहीं; ऐसी जो छात्रों से संबंधी दृष्टि है तो पूरे देश की है। इस प्रकार की दृष्टि विद्यार्थियों के अंदर उत्पन्न करना जरूरी है। इसलिए अखिल भारतीय संगठन विद्यार्थियों का करना यानि Floating population का स्थायी संगठन ये खास विद्यार्थी परिषद् की विशेषता है। इसमें स्थायित्व लाने के लिए जैसे प्राध्यापक उसमें कार्य करते हैं, वैसे ही अनेक लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके विद्यार्थी परिषद् का काम मिशन की तरह करते हैं। यह परंपरा इस संगठन में है और वे नेतागीरी न करते हुए संगठन और विद्यार्थियों के संस्कार की बातें एवं अनुशासन बनाये रखने के लिए काम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का भी उपयोग है। विद्यार्थी परिषद् के नाम के साथ ही अखिल भारतीय नहीं जुड़ा है, बल्कि यह अखिल भारतीय संगठन बना भी है। It was an organization which started at some place but it is now working in all over India including J&K, Andman & Nicobar, Laddakh, Arunachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya, Kerala and everywhere. It is an all India Organisation in real sense.

1970 से आप संगठन मंत्री रहे इस दौरान आपातकाल का दौर भी रहा, संगठन मंत्री के तौर पर आपके क्या अनुभव रहे?

ये तो एक बड़ा अवसर था। ये जो आम धारणा है कि छात्रों की भूमिका केवल कैम्पस तक सीमित है; सही नहीं है। राष्ट्र की तमाम समस्याओं को लेकर छात्रशक्ति की भूमिका है। महंगाई, भ्रष्टाचार एवं तानाशाही के खिलाफ विद्यार्थियों से मिलकर जे.पी. आंदोलन की शुरुआत हुई, इसमें अभाविप को प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हो गया। और उसके बाद देश में जो उथल–पुथल हुआ, आपातकाल आया उसमें पहले एवं बाद में भी अभाविप की भूमिका महत्व की रही। आपातकाल से लड़ने में विद्यार्थियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जेल जाने में, सत्याग्रह करने में, अंडरग्राउंड एक्टिविटी करने में विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय काम किया। उस समय के चुनाव में भी विद्यार्थियों की भूमिका महत्व की रही। परंतु सत्ता परिवर्तन में इतनी बड़ी भूमिका निभाने के बावजूद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् सत्ता में विलीन नही हुआ, क्योंकि उसका काम शिक्षा क्षेत्र में था और वह शिक्षा क्षेत्र एवं छात्रों का संगठन बने रहे और शैक्षिक गतिविधियों में एवं सामाजिक दायित्व अदा करता रहे इसलिए राजनीतिक काम

करना अभाविप के लक्ष्यों में नही रहा। विद्यार्थियों की राजनीति अलग बात है, परंतु देश की राजनीति में विद्यार्थी संगठन काम नही कर सकता, उसके लिए राजनीतिक संगठन काम करते हैं।

Those who wants to go in politics they can go directly, but ABVP is away from political parties. राष्ट्रीय प्रश्नों में, सामाजिक प्रश्नों में, शैक्षिक प्रश्नों में जो उसकी भागीदारी है उसे पूर्ण करने में वह स्वतंत्र स्वायत्त पूर्ण एक विद्यार्थियों का संगठन बना रहे; ये सब करने का देखने का अवसर हमें इस दौरान प्राप्त हो गया। इसलिए 1977 के बाद भी जैसे अन्य विद्यार्थी संगठन राजनीतिक दलों में विलीन हो गए, लेकिन विद्यार्थी परिषद् एक स्वतंत्र संगठन बना रहा और देश में अनेक समस्याओं के लिए लड़ता रहा।

परिषद् में 'ज्ञान, शील, एकता' की बात कही जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय में इसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं?

अच्छी बात है, आरोप लगे हैं तो परिषद् के कार्यकर्ता बरी भी हुए हैं। प्रो. सभरवाल की हत्या के मामले पर फैसला आया है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता निर्दोष साबित हुए हैं। आरोप लगना अलग बात है, इस प्रकार से शुद्ध सोना आग से तपकर बाहर आता है। किसी की व्यक्तिगत गलती नहीं हो सकती ऐसा नहीं है, परंतु अभाविप जैसे संगठन की बात करें इसके अनुशासित व्यवहार के पहलू उजागर हो जाते हैं।

बात 1985 के दिल्ली अधिवेशन की है, हमने विद्यार्थियों के आने के लिए जब रेलवे से अतिरिक्त बोगी की मांग की तो आंदोलनों के संदर्भ में आम धारणा के मुताबिक रेलवे अधिकारियों का जवाब मिला कि –'टिकट के पैसे कौन देगा, फोकट में बोगी थोड़ी लगती है।' हमने कहा कि Everybody has valid tickets, तो अतिरिक्त बोगी हमें मिल गई। उस अधिवेशन में आये हजारों छात्र देश के कोने कोने से अपने पैसे से टिकट लेकर आये थे। इस साल 40 हजार विद्यार्थी किशनगंज गए थे, सभी अपने टिकट लेकर गए। विद्यार्थी परिषद् ने आंदोलनों में भी टिकट लेकर यात्रा करने की प्रथा आरंभ की। विद्यार्थियों का संगठन होते हुए भी अनुशासन और समयबद्धता अभाविप की विशेषता रही है। यह सब बातें अभाविप ने करके दिखाई हैं इसलिए संगठन चल रहा है और बढ़ता जा रहा है।

संख्या विस्तार की होड़ से क्या छात्र संगठनों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है?

हम लोग समाज के अंग हैं। इसी तरह विद्यार्थी परिषद् के 17 लाख सदस्य हैं, उसमें से बात आती है कि विद्यार्थी परिषद् के प्रत्यक्ष कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में नियमित आने वाले छात्र कितने हैं? इसमें से ही कार्यकर्ता बनते हैं। ऐसे यह एक पिरामिड है, उनमें गुण समुच्चय तय होता है। उनका ध्यान सामाजिक गतिविधियों में स्वतः बढ़ जाता है। समाज परिवर्तन एवं व्यक्ति परिवर्तन का कार्य धीरे–धीरे होता है, यह होलसेल में नहीं होता। परंतु जैसा अपना समाज है उसको स्वीकार करने की हमारी मानसिकता है उसको दुरुस्त करने की हमारे प्रयत्न हैं और हमारा ये विश्वास है कि जो जैसा है उसी रूप आ जाये, संगठन में प्रवेश करने के बाद अच्छा बुरा समझ आने पर वह स्वतः बदल जाता है।

अभाविप पर आरोप लगता है कि इसके कार्यकर्ता एक राजनीतिक दल में घुसने के लिए आते हैं,क्या ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें अभाविप कार्यकर्ताओं ने अन्य क्षेत्रों एवं दलों में अपनी जगह बनाई हो?

अन्य दलों में भी है, पीजीआर सिंधिया और कांग्रेस के आनंद शर्मा के नाम इस श्रेणी में गिनाए जा सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम सामने नहीं आ पाते क्योंकि उन क्षेत्रों की चर्चा नहीं होती। राजनीति ही नहीं बल्कि अन्य कई प्रकार के सामाजिक कार्यों में विद्यार्थी परिषद् के लोग जाने चाहिए। जहां विचारधारा का मेल बनता है राजनीति में भी हमारे कार्यकर्ता गए हैं।

स्वाभाविक सी बात है जहां विचारधारा का मेल होगा वहां ज्यादा लोग जाएंगे। अरूण जेटली एवं अनंत कुमार जैसे वर्तमान राजनीतिज्ञ हमारे कार्यकर्ता थे। इसी तरह सहकार भारती के हमारे संगठन मंत्री सूर्यकांत केलकर हैं, सहकार भारती के सह संगठन मंत्री सतीश मराठे हैं, युवा कॉपरेटिव सोसायटी चलाने वाले राजेश पांडेय हैं, वनवासी कल्याण आश्रम के महामंत्री कृपा प्रसाद जी हैं, फिर विकास भारती का काम अशोक भगत और जनजातीय क्षेत्र में सूर्यनारायण सूरी कर रहे हैं। ये लोग बिना प्रसिद्धि की चाह के सालों से काम कर रहे हैं और इनके नाम लोगों को मालूम नहीं है।

कई लोग नये नये प्रयोग चला रहे हैं, आदिवासियों को बैंबू उत्पादों के बारे में तकनीकी प्रशिक्षण देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुनील देशपांडे जंगल में कार्य कर रहे हैं। उनके काम को तो सरकारी स्तर पर भी मान्यता मिल रही है। हमारी इच्छा यही है कि शिक्षा, सेवा, जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ–साथ समाज कार्य में लगें।

शिक्षा के व्यापारीकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

इसके बारे में विद्यार्थी परिषद् निरंतर विचार मंथन कर रही है। वैश्वीकरण के चलते शिक्षा को कोमोडिटी के तौर पर देखा जा रहा है। जिसको खरीदना है वो खरीदे। लेकिन भारत के गरीबों, ग्रामीण जनता, पिछड़े लोगों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना भी जरूरी है। आज जिसके पास पैसा है वही शिक्षा ले सकता है, ऐसा वातावरण बना है। सामान्य लोगों को शिक्षित करने के दायित्व से सरकार पीछे हटती जा रही है, शिक्षा पर बजट कम कर रही है। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। पहले से लोग गरीबी से ग्रस्त हैं और बेकारी एवं वि मता लगातार बढ़ रही है। इस बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। अभाविप के लोग तो लगातार इस पर विचार मंथन एवं आंदोलन कर रहे हैं।

छात्रसंघों के स्वरूप में आप किस तरह का बदलाव महसूस करते हैं?

तब के छात्रसंघ भी ऐसे ही थे। विद्यार्थियों की रोजमर्रा की समस्याओं पर उस वक्त भी कार्य किया जाता था। परंतु विद्यार्थी परिषद् ने जो Participatory भूमिका अदा की वह महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी परिषद् केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए है, यह बात सिद्ध होने लगी। आपातकाल में जब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में थी, असम में घुसपैठ का मामला हो, चाहे शिक्षा परिवर्तन का विषय हो, सभी विषयों पर विद्यार्थी परिषद् आवाज उठाती रही।

इस वर्ष किशनगंज में आंदोलन किया, श्रीनगर में 10 हजार छात्रों ने मार्च किया; विद्यार्थियों में तो देशभक्ति है, उसमें परिवर्तन की ललक है। लेकिन छात्रसंघों का जो स्वरूप बना है, उसमें जरूर राजनीति हावी हुई है। हमारी मांग रही है कि कुछ कानून बनाये जाने चाहिए। कुछ कानून बने भी हैं जिनका हमने स्वागत किया है। फिर भी छात्रसंघ की वह भूमिका अभी भी बनना शेष है जिससे कि हमें और सब लोगों को नाज़ हो।

विद्यार्थी परिषद् के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस अवसर पर आपका क्या संदेश है?

60 वर्ष में जितना विस्तार विद्यार्थी परिषद् ने किया, वह कम नहीं है। पुराने कार्यकर्ता भी कम नहीं हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हम कार्य करते रहें, रचनात्मक कार्यों में शक्ति लगे, राष्ट्र के विकास में लगें इसको लेकर कार्य करते रहना होगा। 60 साल की हमारी ये सम्पत्ति समाज में गई है। जो इतिहास अभाविप का रहा है कि यह एक अनुशासित संगठन है, पदों को लेकर मारपीट नहीं होती, झगड़ेबाजी नहीं होती। ये जो सामूहिकता का आदर्श खड़ा किया है, इन सब बातों को कायम रखना और शिक्षा आज प्रोफेशनल हो गई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की वर्तमान समस्याओं की व्याख्या करते हुए विद्यार्थी परिषद् एक समय की मांग के अनुरूप काम करने वाला संगठन बने और छात्रों एवं समाज की वर्तमान समस्यायों के लिए प्रासंगिक बन सके इसके लिए अपने को तैयार करें, ऐसी आशा आज विद्यार्थी परिषद् से जरूर है। ■

अभाविप ने सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया पर लगाया सवालिया निशान

अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद मराठे ने कहा है कि देशभर में शिक्षा का ना केवल निजीकरण बढता जा रहा है बल्कि उस पर बाजारीकरण हावी होता जा रहा है। पूरी शिक्षा को बडे–बडे उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया है। एबीवीपी इसका पुरजोर विरोध करती है। उनके मुताबिक मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में तो विद्यार्थी परिषद को जमीनी लडाई के साथ–साथ न्याय की लडाई भी लडनी पड़ रही है।

उन्होने न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के डीमेट मामले और छत्तीसगढ में विनायक सेन की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह फैसला सुनाया है वो उस पर सवालिया निशान लगाता है। दशभर में शिक्षा के तेजी से होते बाजारीकरण को गंभीरता से लेते हुए अभाविप की, चार दिवसीय कार्यकारी परिषद बैठक का शुभारंभ करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रायपुर में ये सब कहा।

प्रो. मिलिन्द मराठे ने बताया कि आगामी नौ जुलाई 2009 को एबीवीपी की स्थापना के 60 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन साठ वर्षो में परिषद ने छात्र हित में तमाम कार्यों को अंजाम दिया जो आज मील का पत्थर बन चुके हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन छेडा। जिसके बाद केंद्र को इसे गंभीर मामला स्वीकार करना पडा।

विद्यार्थी परिषद के लगातार आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट में लगाई रिट के चलते अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रावासों की खस्ताहालत को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेजा।

एबीवीपी के महामंत्री विष्णु दत्त शर्मा ने भी कालेजों और दूसरे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में होने वाली रैगिंग को एक गंभीर मामला बताया। उन्होने बताया कि केवल कानून बनाने या दंड देने भर से काम नहीं चलेगा बल्कि इसके लिए संस्थानों से जुडे सभी लोगों को जागरुक होना होगा। सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। केवल तभी इस पर काबू पाया जा सकता है।

प्रो. मिलिन्द मराठे ने बताया कि लोकसभा चुनावों के पहले विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश में युवा मतदाता जागरण अभियान चलाया जिसमें युवाओं को जाति–धर्म–संप्रदाय से ऊपर उठकर मतदान करने का आव्हान किया। उन्होने केंद्र में स्थिर सरकार लाने और सत्ता पाने की लालसा रखने वालों के बीच किंगमेकर की भूमिका निभाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। परिषद् की बैठक को सम्बोधित करने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मा.मोहन भागवत भी पहुंचे। ■

Stop Commercialisation, Include Moral Education - ABVP

Despite having the pressure of making good career and study the students must do something concrete for the country," said ABVP national president Prof Milind Marathe. He was addressing a gathering of more than one thousand students at Kolkata's famous Mahajati Sadan Auditorium on July 9.

The function was organised by ABVP Kolkata unit to commemorate the completion of 60 years. Shri Marathe strongly criticised the commercialisation of education by educational institutions in the name of providing quality education, which is beyond the capacity of majority of the countrymen. He said character, patriotism and samskars are not being included in the curriculum at all. Sri Nripendra Krishna Acharya, said our colonial education system did not have the curriculum to make a man of character, a man who has high values and a man of good conduct.

नशीली स्मृतियाँ

– राजकुमार भाटिया –

अभाविप कार्यकर्ता के नाते मेरा कार्यकाल बहुत लम्बा रहा। संगठन में मुझे दिल्ली प्रदेश मंत्री का दायित्व उस वर्ष (1967) में मिला जिस वर्ष से उसे अखिल भारतीय संगठन बनाने का गंभीर प्रयास शुरू हुआ। विद्यार्थी, विद्यार्थी विस्तारक, पूर्णकालिक एवं प्राध्यापक के विभिन्न रूपों में 41.5 वर्ष के इस कार्यकाल में जहां मुझे परिषद् के अनेक ऐतिहासिक अवसरों एवं मील के पत्थरों का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला वहीं अनेक खट्टे–मीठे, रोचक व रोमांचक अनुभव भी प्राप्त हुए।

ऐतिहासिक अवसरों में प्रथम थे गुजरात व बिहार आन्दोलन जिनकी परिणति श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में हुई। भारतीय छात्र आन्दोलन के इतिहास का यह स्वर्णिम काल था। संपूर्ण आदोलन में परिषद् की मुख्य भूमिका थी और परिषद् के सक्रिय कार्यकर्ता और महामंत्री के नाते मेरा भी उससे संबंध रहा। आन्दोलन के परिणामस्वरूप देश में 21 मास का आपातकाल लागू किया गया और तानाशाही शासन थोपा गया। तानाशाही का सबसे कठोर दण्ड था मीसा बंदी बनाया जाना। 19 मास मुझे भी बंदी बनना पड़ा।

कालक्रम में ऐतिहासिक अवसर बने। अभाविप की स्थापना की रजत जयन्ती व स्वर्ण जयन्ती। दोनों के भव्य आयोजन क्रमशः 1974–75 और 1998–99 में हुए। मुझे दोनों में सहभागी होने का अवसर मिला।

मील के पत्थरों की चर्चा करूँ तो परिषद के अनेक प्रथम आयोजनों में मैं सहभागी बना। वे थे 1968 में मुम्बई में हुआ परिषद् का प्रथम अ.भा. अभ्यासवर्ग, 8 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में 1970 में दिल्ली में हुआ प्रथम अ.भा. प्रदर्शन, 1971 के मध्य में देश के विभिन्न नगरों में हुए प्रथम क्षेत्रीय अभ्यास वर्ग जिनमें मुझे भी रहने का अवसर मिला। श्री यशवंतराव केलकर के निवास पर मुम्बई में जनवरी 1972 में हुई प्रथम राष्ट्रीय टीम बैठक व 1982 में आबू में हुई प्रथम विचार बैठक, एक भिन्न प्रकार का मील का पत्थर था।

1994 में मेरा अमरीका का 4 सप्ताह का प्रवास। अमरीकी सरकार सोच समझकर कुछ लोगों को अपने देश में प्रवास के लिए आमंत्रित करती है । परिषद का मैं प्रथम, और अब तक का अंतिम

पदाधिकारी (राष्ट्रीय अध्यक्ष) था जिसे आमंत्रित किया गया।

परिषद् में मुझे दो सौभाग्य भी प्राप्त हुए। परिषद के निर्माण में जिन दो व्यक्तियों का सर्वाधिक योगदान रहा वे थे स्व. प्राध्यापक यशवंतराव केलकर व श्री मदन दास। दोनों का दीर्घ सान्निध्य प्राप्त होना मेरा प्रथम सौभाग्य था। 1967 से 1987 तक मुझे श्री केलकर जी का साथ मिला, 1970 में श्री मदनदास जी जब राष्ट्रीय संगठन मंत्री बने तब मैं महामंत्री बना। 4 वर्ष इस प्रकार हमारा साथ रहा। तत्पश्चात मदनदास जी 18 वर्ष और संगठन मंत्री रहे जबकि मेरे दायित्व बदलते रहे पर हमारा साथ सदा बना रहा।

मेरे कुछ रिकॉर्ड भी बने। मैं परिषद का महामंत्री भी बना और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। संभवतः परिषद के सर्वाधिक अधिवेशनों में सहभागी होने वाला मैं प्रथम व्यक्ति हूँ। इनमें वामपंथियों के गढ़ कलकत्ता व त्रिवेन्द्रम में क्रमशः 1969 व 1970 में होने वाले अधिवेशन सम्मिलित थे तो 1971 और 1985 में दिल्ली में आयोजित वे बड़े अधिवेशन भी थे जिनकी पूरी तैयारी में मुझे जुटना पड़ा।

परिषद् की स्थापना की रजत जयन्ती व स्वर्ण जयन्ती वर्षों के अधिवेशन मुम्बई में क्रमशः 1974 व 1998 में हुए। दोनों में मैं सहभागी हुआ। उसी प्रकार परिषद् का 25वाँ व 50वाँ, दोनों अधिवेशन जयपुर में हुए। मुझे उनमें भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। परिषद के अन्य बड़े अधिवेशनों के अतिरिक्त दो बड़े अधिवेशन 1982 (नागपुर) और 1992 (कानपुर) में हुए। मैं उनमें भी सहभागी बना। 2001 व 2002 में क्रमशः सुदूर पूर्व (गुवाहाटी) व सुदूर दक्षिण (कालीकट) में अधिवेशन हुआ। मुझे उनमें भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

परिषद के मेरे जीवन का रोमांच एवं महत्वपूर्ण पक्ष रहा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव। जब मैं परिषद में नया ही था और न चुनावों में मेरी रूचि थी ओर न ही चुनाव लड़ने लड़ाने का मेरा कोई अनुभव था तब देश के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनाव में अभाविप प्रत्याशियों के चुनाव संचालन में मुझे भाग लेना पड़ा। 1968 से 1972 तक अप्रत्यक्ष व बाद में प्रत्यक्ष, ऐसे 30 से अधिक चुनावों के आयोजन में मुझे लगना पड़ा। 1971 से परिषद की जीत प्रारंभ हुई, 1978 से 1981

तक वह चुनाव से बाहर रही तो 1982 से 1989 तक वह भाजपा के छात्र मोर्चे जनता विद्यार्थी मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी।

परिषद के कारण मुझे एक बोधप्रद एवं समाजोपयोगी प्रथा का ज्ञान हुआ। दक्षिण भारत में व्यक्ति की आयु 60 वर्ष की होने पर उसकी षष्टीपूर्ति मनाए जाने की प्रथा प्रचलित है। मुझे इस प्रथा का प्रत्यक्ष अनुभव तब आया जब 1985 में आविप द्वारा मुख्यतः महाराष्ट्र में तथा देश में कुछ स्थानों पर प्राध्यापक यशवंतराव केलकर की षष्टीपूर्ति मनाई गई। उसके बाद परिषद् के अन्य कुछ प्रमुख लोगों के लिए भी ऐसे आयोजन हुए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अभाविप, दोनों में हमें यह संस्कार मिलता है कि पद और यश की आकांक्षा के बिना सामाजिक कार्य करना चाहिए। उसी संस्कार के चलते किसी व्यक्ति के गुणगान को भी अनुचित माना जाता है। परंतु यदि कोई सामाजिक कार्यकर्ता अनुकरणीय रहा हो और उसकी आयु का बड़ा भाग पूर्ण हो चुका हो तो ऐसे अवसर पर उसका सम्मान होना सर्वथा उपयुक्त सामाजिक क्रिया होती है। इसी सोच के कारण षष्टीपूर्ति आयोजन मुझे बहुत सुसंगत लगते हैं तथा ऐसे आयोजनों में मैं उत्साहपूर्वक भाग लेता हूँ।

परिषद् में एक और रोमांचक अनुभव था मेरी पहली हवाई यात्रा। परिषद में हमें निःस्वार्थी सामाजिक कार्य, प्रसिद्धी पराउन्मुखता, सादगी और मितव्ययिता के संस्कार भी प्राप्त होते हैं। मितव्ययिता के संस्कार के कारण हम मंहगी यात्रा करना टालते हैं। उसी संस्कार का परिणाम था कि आयु के 43 वर्ष व परिषद कार्य के 23 वर्ष पूरे करने के पश्चात् मुझे प्रथम हवाई यात्रा करने का अवसर मिला,जब एक बैठक हेतु मैं हैदराबाद गया। ■

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक

रायपुर (छत्तीसगढ)

अभाविप के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक दिनांक 27 से 30 मई, 2009 को रायपुर (छत्तीसगढ़) में सम्पन्न हुई। बैठक का संचालन अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मिलिंद मराठे व राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा ने संयुक्त रुप से किया। बैठक में कुल अपेक्षित 262 सदस्यों में से 188 सदस्य उपस्थित रहे।

गत वर्ष हुए संगठनात्मक विस्तार तथा विकास के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय अभियानों व आन्दोलनों की समीक्षा एवं राष्ट्रीय, प्रांतीय कार्यक्रमों आदि की चर्चा के साथ वर्तमान राष्ट्रीय व आगामी दिशा के संदर्भ में व्यापक चर्चाएँ संपन्न हुई। देश की वर्तमान परिस्थिति एवं शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य जैसे विषयों पर प्रस्ताव तथा आगामी अभियान व कार्यक्रमों के निर्णयों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

दिनांक 27 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मिलिंद मराठे व राष्ट्रीय महामंत्री श्री विष्णुदत्त शर्मा द्वारा दीप प्रज्जवलन एवं वंदेमातरम् गायन से बैठक का शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात अभाविप के प्रथम राष्ट्रीय महामंत्री श्री केशव देव वर्मा के निधन (17 मई, 2009) पर मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजली दी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के वास्तविक व अभाविप के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, अतिथियों के परिचय के पश्चात पिछली रा.का.प. (जलगाँव राष्ट्रीय अधिवेशन से पूर्व व पश्चात) बैठक का संक्षिप्त वृत्त केन्द्रीय कार्यालय मंत्री श्री भरत सिंह ने रखा, जिसे सदस्यों ने पारित किया ।

बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक मा. मोहनराव भागवत विशेष रूप से सहभागी हुए एवं रा.का.प. के सभी सदस्यों का मार्गदर्शन किया । अभाविप के 60 वर्ष पूर्ती पर आनंद वक्त करते हुए संगठन की गुणवत्ता के प्रति सजग रहने का आहवान उन्होंने इस निमित्त किया।

29 मई को छत्तीसगढ़ के पूर्व कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित हुआ । जिसमें मा. सुरेश सोनी (सह सरकार्यवाह, रा.स्व.संघ), अभाविप के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. राजकुमार भाटिया (सचिव, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद) एवं श्री सुनील आंबेकर (राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अभाविप) विशेष रूप से उपस्थित रहे। दिनांक 29 मई को सांयकाल आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोह के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के विकास व नक्सलवाद के सफाये का संकल्प दोहराया । कार्यक्रम में मिलिंद मराठे व श्री विष्णुदत्त शर्मा ने अभाविप की देशभर में गतिविधियों व उपलब्धियों का जिक्र करते हुए शहर के गणमान्य नागरिकों को सम्बोधित किया । कार्यक्रम के मंच पर विशेष रूप से स्वागत समिति के अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. अरूण दाबके (कुलपति) व विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ के प्रांत अध्यक्ष डॉ. किर्तन कुमार साहु तथा प्रांत मंत्री श्री संजीत सिंह उपस्थित रहे।

बैठक में वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा करते हुए शिक्षा क्षेत्र में बढ़ता व्यापारीकरण, विभिन्न स्थानों पर हुई रैगिंग की शर्मसार घटनाएँ, राजनीति में वंशवाद का विस्तारीकरण, पड़ोसी देशों में हाल ही में घटित घटनाएँ एवं नवगठित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार आदि विषयों पर बैठक में चर्चा हुई।

रा.का.प. बैठक में संगठनात्मक कार्य की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर ने चर्चा का संचालन किया। वर्ष 2008–09 की संगठनात्मक जानकारी सब के सामने रखी ।

विस्तार को स्थिर करने के उपायों के बारे में चर्चा करते हुए भविष्य में कार्य के विस्तार की प्रक्रिया में विद्यार्थी व प्राध्यापक कार्यकर्ताओं के अधिक सहभाग की आवश्यकता चर्चा से उभर कर सामने आयी । महाविद्यालय इकाईयों की सक्रियता पर भी जोर दिया गया।

राष्ट्रीय व स्थानीय कार्यक्रमों के स्वरूप, सहभाग व परिणामों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा हुई।

शैक्षिक, राष्ट्रीय व विभिन्न मुद्दों पर पिछले वर्ष अभाविप द्वारा चलाये गये आंदोलनों की समीक्षा करते हुए भविष्य में व्यापक विद्यार्थी सहभाग व परिणामकारी आंदोलन हो ऐसा विषय उभर कर आया।

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में शिक्षा का

वर्तमान परिदृश्य और देश की वर्तमान परिस्थिति पर दो प्रस्ताव सर्वसम्मति से परित हुए ।

डॉ. एम. चैत्र (महासचिव, विश्व विद्यार्थी युवा संघ) ने WOSY की गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु युवाओं की भूमिका को देखते हुए फरवरी, 2010 में प्रस्तावित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा पूणे में होने वाली केन्द्रीय समिति की बैठक की जानकारी दी ।

प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल के महासचिव श्री नारायण ढकाल भी बैठक में विशेष निमन्त्र पर सहभागी हुए। उन्होंने अपने संगठन की गतिविधियों के बारे में रा. का.प. के सदस्यों को अवगत कराया ।

राष्ट्रीय सह–संगठनमंत्री श्री के.एन. रघुनंदन ने देशभर की शैक्षणिक सांख्यिकी (कुल विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अध्यापक, छात्र आदि) सभी सदस्यों के सामने रखते हुए शिक्षा प्रकोष्ठ की उपयोगिता एवं आगे की योजना, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट, प्रांतशः वर्तमान शैक्षिक शुल्क संरचना आदि विषयों पर चर्चा की ।

श्री सुनील आंबेकर (राष्ट्रीय संगठन मंत्री) ने पिछले वर्ष हुबली में हुई रा.का.प. की बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 60 वर्ष पूर्ती अभियान 9 जुलाई 2009 से 9 जुलाई 2010 तक चलेगा। इनहोंने बताया कि संगठन के विस्तार की दृष्टि से अभाविप विचार व उपलब्धियाँ व्यापक रूप से सामान्य छात्र व समाज तक पहुँचाना है। इस निमित्त गठित समिति के सुझावों को श्री सुनील बंसल ने रखा एवं साहित्य निर्माण समिति के प्रमुख श्री गोपाल शर्मा ने प्रस्तावित साहित्य के बारे में जानकारी दी।

संस्कृति–2009 (केरल), निःशुल्क शिक्षा शिविर (बिहार), शोध छात्र सम्मेलन (हिमाचल प्रदेश), आदर्श महाविद्यालय इकाई (हजारीबाग, झारखंड), विधि छात्रों हेतु निःशुल्क कक्षाएँ (दिल्ली) एवं आदर्श नगर इकाई आदि विशेष कार्यक्रमों के वृत्त भी प्रांतों से प्राप्त हुए ।

युवा विकास केन्द्र (YVK) :– युवा विकास केन्द्र, गुवाहाटी में दिनांक 6–8 अप्रैल, 2009 को आवासीय भवन का लोकार्पण कार्यक्रम एवं शहर में एक अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम संपन्न हुआ ।

छात्रा कार्य :– इस वर्ष छात्रा सदस्ययता 5,13,990 है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सदस्यता बढी है । 6 प्रांतों में 242 महिला महाविद्यालयों में संपर्क तथा 14 प्रांतों में प्रांत प्रमुख तय हैं ।

आगामी कार्यक्रम एवं निर्णय :–

55वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन :– अभाविप का 55वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन ऊना (हिमाचल प्रदेश) में 30–31 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2009 को होगा ।

बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी आंदोलन :– श्री बी. सुरेन्द्रन (राष्ट्रीय सह– संगठन मंत्री) ने चर्चा का संचालन करते हुए बताया कि केन्द्र सरकार ने विद्यार्थी परिषद के मुद्दों का स्वीकार किया है तथा लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में इस विषय पर चर्चा हुई है सीमा पर नये चेक पोस्ट बनाने व मेघालय की सीमा पर तारबंदी के लिए निधि का प्रावधान हुआ है। आंदोलन के अगले चरण में केन्द्र सरकार व प्रांत के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन देना है । एवं घुसपैठियों की पहचान व मतदाता सूची से उनक नाम हटाने हेतु सरकार पर दबाव बनाना है ।

प्रदेश मंत्री कार्यशाला :– दि. 30–31 जुलाई, 2009 को भोपाल में प्रदेश मंत्री कार्यशाला का आयोजन होगा, जिसमें सभी राष्ट्रीय मंत्री, प्रदेश मंत्रियों के साथ प्रत्येक प्रांत के मीडिया (समाचार माध्यम) से संबंधित एक प्रमुख कार्यकर्ता अपेक्षित है।

शिक्षा कार्यशाला :– शिक्षा के विभिन्न विषयों पर प्रबोधन एवं सहमति बनाने के उद्देश्य से शिक्षा कार्यशाला का आयोजन दिनांक 14–15 फरवरी, 2010 में मुम्बई में प्रस्तावित है । प्रांतों के प्रमुख पदाधिकारी व शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रमुख कार्यकर्ता अपेक्षित रहेंगे ।

अ.भा. विचार बैठक :– अभाविप की अखिल भारतीय विचार बैठक दिनांक 2 से 4 अप्रैल, 2010 में होना निश्चित है ।

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक से पूर्व 27 मई को प्रातः अभाविप के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में रा.का.प. बैठक की विषय सूची, प्रस्ताव व अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई ।

रा.का.प. बैठक में 29 मई को 'वैश्विकरण और आर्थिक मंदी' पर श्री एम.आर. वेंकटेश (चेन्नई) का भाषण हुआ तथा बाद में प्रश्नोत्तर भी हुआ।

रा.का.प. बैठक के व्यवस्था प्रमुख श्री संजय जोशी ने व्यवस्था व उसमें लगे सभी प्रबंधक कार्यकर्ताओं का संक्षिप्त परिचय कराया । जिसका सभी प्रतिनिधियों ने करतल ध्वनि से अभिनंदन किया । ■

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में पारित प्रस्ताव

शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य

वर्तमान समय में देश का शिक्षा क्षेत्र पूरी तरह से बाजारीकरण की चपेट में है। प्रारंभिक से उच्च शिक्षा (KG to PG) तक सभी प्रकार की शिक्षा चाहे वह इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबन्धन आदि के पाठयक्रम हों या फिर विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा पाठयक्रम इन सब में बढ़ता बाजारीकरण सामान्य एवं निर्धन छात्रों को शिक्षा से दूर ले जाता हुआ नजर आ रहा है । यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको तत्काल रोकने के प्रयास आवश्यक हैं ।

शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते बाजारीकरण को रोकने के लिए देश में किसी प्रकार का कोई कानून नही है । अपितु AICTE, NCTE, MCI जैसी नियामक संस्थाओं की अनुशंसाएं भी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से बाजारीकरण को बढ़ावा देने में ही सहयोग कर रही हैं। वहीं दूसरी और देश में निजीकरण के नाम पर सरकारी महाविद्यालय, वि.वि. में Self Financing Seats शुरू होना प्रतिभावान परंतु गरीब छात्रों से उच्च शिक्षा के अवसर को भी छीन रहा है। इस तरह से शिक्षा में बढ़ता बाजारीकरण समाज में विभेद निर्माण करने वाला सिद्ध हो रहा है। इसलिए अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद देश में शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के लिए तुरंत केन्द्रीय कानून लाने की पुरजोर मांग करती है

अभी देश में उच्च शिक्षा के आयु समूह (18–24) का सकल नामांकन 10.67 प्रतिशत है जिसको बढ़ा कर कम से कम 15 प्रतिशत करने की अनुशंसा अनेक शिक्षा विदों और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने की है। लेकिन इस तीव्र बाजारीकरण के कारण मंहगी होती शिक्षा से बड़ी संख्या में छात्र चाहते हुए भी उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात बाजारीकरण का परिणाम सिर्फ मंहगी शिक्षा के कारण से निर्धन छात्रों के शिक्षा ग्रहण करने में बाधा के रूप में ही नहीं है अपितु उच्च शिक्षा में अपेक्षित संख्या का नामांकन न होने के कारण बाजारीकरण राष्ट्रीय विकास को भी बाधित करेगा।

हालांकि तीव्र बाजारीकरण के इस दौर में भी अपवाद स्वरूप कुछ राज्य सरकारों ने शुल्क में कमी के अनेक उपाय किये हैं उदाहरणार्थ कनार्टक सरकार ने निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में निर्धारित शासकीय कोटे की सीटों पर शुल्क में कमी करते हुए उसे 15,000 रू. तक ले आने का अभिनंदनीय कार्य किया है। एक और सरकारें उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा से अपने हाथ खींच रही हैं वहीं कनार्टक सरकार के द्वारा शासकीय क्षेत्र में एक वर्ष के भीतर 8 मेडिकल महाविद्यालय, 15 इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 150 डिग्री महाविद्यालय, 300 जूनियर महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। जो निर्धन छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से प्रशंसनीय हैं। कर्नाटक सरकार के द्वारा किये गये प्रयासों से यह स्पष्ट है कि सरकारें यदि चाहें तो बाजारीकरण की तीव्र प्रक्रिया पर अंकुश लगाया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद भारत एवं केन्द्र सरकारों से यह मांग करती है कि कनार्टक के तर्ज पर उच्च शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण पर रोक लगाने हेतु सकारात्मक पहल करें।

शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ विद्यार्थी परिषद द्वारा मध्य प्रदेश में विगत तीन वर्ष से चल रहे क्मदजंस – डमकपबंस म्दजतंदबम ज्मेज के आंदोलन को उस समय सफलता मिली थी जब माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रवेश परीक्षा सरकार को ही करानी चाहिए । यह एक अभिनंदनीय निर्णय था, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगनादेश देने के बाद निजी एवं शासकीय कोटे में 50–50 प्रतिशत सीटों का आवंटन जैसा निर्णय देकर बाजारीकरण को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं ।

देश के कई प्रांतों में मानित एवं निजी विश्वविद्यालयों (Deemed University and Private University) की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है । देश में कुल 138 मानित विश्वविद्यालयों में से 57 विश्वविद्यालय गत तीन वर्ष में शुरू किये गये हैं और लगभग 229 मानित विश्वविद्यालयों के मामले विचाराधीन

हैं । इनमें से अधिकांश सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा के ऐसे संस्थान हैं जिनकी किसी विशेष क्षेत्र में कोई स्थापित प्रतिष्ठा नही है जो कि मानित विश्वविद्यालय के मूलभूत संकल्पना का उल्लंघन है। इन विश्वविद्यालयों को मानित (Deemed) शब्द लगाने की अनिवार्यता से मुक्ति देकर के केन्द्र सरकार ने (Deemed University) अवधारणा को ही समाप्त कर दिया है। इससे आम छात्र विश्वविद्यालय एवं मानित विश्वविद्यालय के बीच का अंतर न समझकर बाजारीकरण का शिकार होगा। इसके साथ–साथ हाल ही में यूजीसी द्वारा 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों की आनन–फानन में नियुक्तियां कर प्रत्येक कुलपति की निजी खातों में पांच–पांच करोड़ रूपये हस्तांतरित करना संदेहास्पद लगता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने मद्रास विश्वविद्यालय के 151वें दिक्षांत कार्यक्रम के भाषण में यह मान्य किया है कि मानित विश्वविद्यालय शैक्षिक उत्कृष्टता प्रदान करने के बजाये केवल पैसा कमाने का माध्यम बन गए हैं उन्होंने यह भी आवश्यकता व्यक्त की है कि मानित विश्वविद्यालयों को कड़े जाँच में रखना चाहिए ।

इसके साथ ही कुलाधिपति ने अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मानित विश्वविद्यालय न बनाने का सुझाव भी दिया है क्योंकि यह संस्थाएं मानित विश्वविद्यालय होने के बाद अल्पसंख्यक संस्था के रूप में केन्द्र तथा राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद इस चिंता से सहमति व्यक्त करती है तथा इस मांग को दुहराती है कि मानित एवं निजी विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने हेतु सक्षम राष्ट्रीय नियामक आयोग बनाया जाये।

इस प्रकार देश में निजी विश्वविद्यालयों के बारे में कोई निश्चित नियम नहीं होने के कारण निजी विश्वविद्यालय आये दिन दुकानों की तरह खुल रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा छोटे से पहाड़ी राज्य में 15 निजी विश्वविद्यालयों की घोषणा की गई हैं। इनमें से पांच को मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही भी हो गई है। आनन–फानन में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना देश के सभी राज्यों में हो रही है । इसमें से अधिकतर निजी विश्वविद्यालय बाजार की आवश्यकतानुसार व्यवसायिक पाठयक्रम मनमर्जी का शुल्क वसूलकर चलाते हैं । सरकारों की दिशाहीन शिक्षानीति इस प्रकार के बाजारीकरण को बढ़ावा देती है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है ।

देशभर में कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया अस्पष्ट तथा संदेहास्पद है। राजनीतिक दखलांदाजी और राजनैतिक निष्ठा के आधार पर कुलपतियों की नियुक्ति ने विश्वविद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था को गंभीरता से प्रभावित किया है। इस संबंध में स्पष्ट, पारदर्शी एवं तटस्थ नियुक्ति प्रक्रिया की मांग लगातार होती रही है। किन्तु मांग के पूरा करने के बजाय लगातार राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिये गठित तथाकथित सर्च कमेटी के द्वारा सिर्फ दो दिन के अंदर 1500 आवेदन पत्रों की जाँच करके 13 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति की सिफारिश करना तथा आनन–फानन में नियुक्ति पत्र का जारी होना, एक स्वतंत्र एवं गंभीर जाँच का विषय है ।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कुलपति चयन के लिए एक बिल्डर को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा नामांकित करना, म.प्र. में ही एक बहुचर्चित भ्रष्ट, नकलची कुलपति के खिलाफ म.प्र. उच्च न्यायालय मे आरोप सिद्ध हो जाने पर कार्यवाही के लिए आदेश आना आदि कुलपति चयन प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। म.प्र. सहित उ.प्र. आदि राज्यों में अनेक विश्वविद्यालयों में अनेक विश्वविद्यालयों के कलपतियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं। अतः विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद यह मांग करती है कि कुलपतियों की नियुक्ति हेतु बिना देरी किए एक तटस्थ और पारदर्शी चयन व्यवस्था बनायी जाय ।

हाल ही में हिमाचल प्रदेश मे घटित रैगिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रैगिंग करने वालों पर कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय दिया है जिसका स्वागत है । किंतु विद्यार्थी परिषद का यह मत है कि केवल कानून मात्र बनाने से समस्या हल नहीं होगी । रैगिंग के पीछे मानसिकता एवं परिवेश कारक होता है इसका परिवर्तन छात्रों के बीच जागरूकता निर्माण एवं सामाजिक दृष्टि के विकास से ही संभव है अर्थात इसके लिए जागृति के सुधारात्मक कदम अधिक अपेक्षित हैं ।

इस हेतु छात्रों के बीच में आवश्यक रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित हों तथा महाविद्यालयों में छात्र संघ जैसी लाकतांत्रिक प्रक्रिया अनिवार्य किया जाय । जिससे

रैगिंग जैसी बुराइयों को रोकने में मददगार होंगी ।

संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र की पुनर्रचना तथा नई व्यवस्था के निर्माण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में "Committee to Advice on Renovation and Rejuvenation of Higher Education" का गठन किया था, इसके पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी ज्ञान आयोग नामक सम्पूर्ण आयोग ही बनाया था। दोनों ही रिपोर्ट में शिक्षा क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की संस्तुति की है. एक तरह से यह विद्यार्थी परिषद् द्वरा लंबे समय से की जा रही मांग की स्वीकृति है किंतु दोनों ही समितियों के बाद प्रस्थापना को लेकर भ्रम का निर्माण हुआ है । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकारी परिषद की यह मांग है कि इन दोनों के बीच बने भ्रम एवं विरोध को दूर करते हुए सरकार शिक्षा को नियमित करने वाले स्वायतशासी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की शीघ्र स्थापना करें ।

शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ राष्ट्रवादी आन्दोलन की आवश्यकता का अनुभव करते हुए अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद देश के छात्रों से इसका सशक्त प्रतिरोध करने का आह्वान करती है ।

देश की वर्तमान परिस्थिति

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र में नये जनादेश के आधार पर गठित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की नई सरकार का स्वागत करती है, वर्तमान जनादेश का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि खंडित जनादेश के आधार पर राजनीति में ब्लेकमेलिंग और नीति निर्धारण में अनावश्यक और गैर जिम्मेदाराना दखलअंदाजी भी कम हो जायेगा। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम व सिंगुर तथा केरल के कन्नुर में साम्यवादियों की हिंसा के विरोध में देश की जनता का जनादेश स्वस्फूर्त रहा जिसने साम्यवादियों को वर्तमान लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंका है। जनता ने इसके साथ ही अपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को भी नकारा है । कार्यकारी परिषद् का यह भी मानना है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ समझने जाने वाले मीडिया ने जिन युवाओं को देश के युवा नेतृत्व के नाम पर प्रचारित किया है वे दुर्भाग्य से युवाओं के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं होकर वंशवाद के विस्तारीकरण के प्रतिनिधि अधिक हैं । विद्यार्थी परिषद का मानना है कि राजनीति सहित राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में वास्तविक युवा नेतृत्व उभर कर आना चाहिए ।

नक्सलवाद भारत के विभिन्न प्रांतों में अत्यन्त गंभीर रूप धारण करता जा रहा है । यद्यपि 15वीं लोकसभा के चुनाव में नक्सलवादियों के चुनाव बहिष्कार के आह्वान को अस्वीकार करते हुए उनके प्रभावित क्षेत्र की जनता ने भी चुनाव में बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी की। यह इस तथ्य का सुखद सकते है कि हिंसक नक्सलियों को आम आदमी का समर्थन हासिल नहीं है । भारत की आंतरिक सुरक्षा और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए खतरनाक नक्सलियों ने गत वर्षों में देश के विविध हिस्सों में भयंकर रक्तपात एवं हिंसा की है । महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक जांबाज पुलिस ऑफिसर सहित 16 पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या नक्सलवादियों द्वारा की जाने वाली वारदातों का एक ज्वलंत उदाहरण है । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नक्सवादी हिंसा में शहीद पुलिस कर्मियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केन्द्र सरकार से यह मांग करती है कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अंतर-प्रातीय कार्ययोजना बनाकर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करे ।

स्विस बैंकिंग एसोसिएशन रिपोर्ट 2006 में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि भारत का लगभग 70 लाख करोड रूपया (1456 बिलियन डॉलर) स्विस बैंकों के गोपनीय खातों में जमा है तथा यह काले धन के रूप में भारत से बाहर ले जाया गया है । यह तथ्य अधिकृत रूप से फरवरी 2008 से भारत सरकार की जानकारी में भी आ चुका है । अ.भा.वि. परिषद की यह कार्यकारी परिषद केन्द्र सरकार से मांग करती है कि विदेशों में जमा इस धन को वापस लाने के साथ ही जमा करने वालों के नाम भी देश की जनता के समक्ष सार्वजनिक किया जाए । भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका के उत्तर में सरकार की ओर से यह स्वीकार भी किया गया है ।

परन्तु अभी तक भारत सरकार ने इस धन को वापस भारत लाने की दिशा में कोई ठोस प्रयास नही किया है। जबकि स्वीट्जरलैंड के नियमों के अनुसार संबंधित देश की सरकारें यदि चाहें तो गोपनीय खातों में जमा काला धन वापिस ले सकती हैं । विद्यार्थी परिषद का यह भी मानना है कि बोफोर्स घोटाले के मुख्य अभियुक्त क्वात्रोची को जो सी.बी.आई. ने क्लीन चिट दी है वह भ्रष्टाचार को सरकार का समर्थन देने का उदाहरण तो है ही सरकारों द्वारा सी.बी.आई. के दुरूपयोग को प्रमाणित करता है ।

विद्यार्थी परिषद की यह कार्यकारी परिषद बैठक भारत के पडोसी देशों में हाल ही में घटित घटनाओं पर चिंता व्यक्त करती है । भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में लंबे समय से चल रहे श्रीलंका सेना व LTTE के बीच का युद्ध LTTE के खात्मे के साथ समाप्त हो गया। यह कई दशकों से चल रहे सशस्त्र संघर्ष का अंत है, किन्तु इस युद्ध में विस्थापित हताहत सामान्य तमिलजनों के पुनर्वास के प्रयत्न के साथ वहां के मूल तमिलों के मानवीय अधिकार की रक्षा की जाय तथा उनको समानता एवं स्वतंत्रतापूर्वक उनकी भाषा, संस्कृति तथा उपासना पद्धति उपयोग के अधिकार बहाल किये जायें। अभाविप भारत सरकार से यह मांग करती है कि इस दृष्टि से सरकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें।

चीन के द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक (Asian Development Bank) को यह पत्र लिखा जाना है कि अरूणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र है, स्पष्टतः भारत की संप्रभुता पर चोट पहुँचाना है । इसका कठोर प्रतिकार करना भारत सरकार का कर्तव्य है । चीन के इस दुष्कृत्य की कठोर भर्त्सना करते हुए अभाविप की कर्यकारी परिषद् भारत सरकार से मांग करती है कि चीन द्वारा कब्जे में लिये गये भारतीय जमीन के हिस्से को वापस लेने के लिए निर्णायक प्रयास करे । स्वातघाटी में तालिबानों के कब्जे ने यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान पूर्णतः चरमपंथी इस्लामिक आतंकवाद के कब्जे में आ चुका है ।

स्वयं पाक राष्ट्रपति जरदारी की यह स्वीकारोक्ति की तालिबानियों को अमेरिका व पाकिस्तान के खुफिया एजेन्सियां, सी.आई.ए. एवं आई. एस.आई. ने बढ़ावा दिया है, यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को संरक्षण देने का कार्य निरंतर चलता रहा है । जिसने भारत सहित पूरी दुनिया के समक्ष आतंकवाद का भयंकर खतरा उत्पन्न कर दिया है । तालिबान एवं आतंकवादियों का प्रतिकार पाकिस्तान सरकार के द्वारा दिखावे के बजाय ईमानदारीपूर्वक करना चाहिए । माओवादी छापामारों को नेपाल की सेना में शामिल करने के प्रश्न पर प्रचंड सरकार और वहाँ के सेनाध्यक्ष के बीच मतभेद के चलते जिस प्रकार लोकतंत्र विरोधी माओवादी सरकार का पतन हुआ है यह नेपाल में लोकतंत्र की जीत ही है । नेपाल की नई सरकार का स्वागत करते हुए अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् विश्वास व्यक्त करती है कि श्री माधव नेपाल के नेतृत्व में गठित नई नेपाल सरकार और नेपाल के प्रगाढ़ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रिश्तों को और अधिक मजबूत करेगी ।

पिछली संप्रग सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए देश की जनता के सामने कुछ प्रयासों की घोषणा की थी जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत बनाना, तटीय कमान की स्थापना करना, आतंकवाद विरोधी कानून बनाना, फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करना एवं राष्ट्रीय जांच एजेन्सी की स्थापना करना आदि सम्मिलित हैं ।

एक ओर इन घोषणाओं का क्रियान्वयन बाकी है तथा देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने बंगलादेशी घुसपैठियों पर कोई कार्यवाही न होना तो दूसरी और सर्वोच्च न्यायालय से सजा प्राप्त अफजल जैसे आतंकवादी को अभी तक फाँसी नहीं दिया जाना देश की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार के प्रयासों की ईमानदारी पर संशय खड़ा करता है । इस बीच नई सरकार ने 100 दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कमांड के गठन का वायदा भी किया है, विद्यार्थी परिषद् की यह कार्यकारी परिषद् इसका स्वागत करती है तथा इन घोषणाओं के तुरन्त क्रियान्वयन की मांग करती है ।

अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद एक बार फिर नवनिर्वाचित सरकार से यह अपेक्षा करती है कि सरकार जनता से किये विकास व राष्ट्रीय सुरक्षा के वायदों को पूरा करेगी और अब तक की तुष्टीकरण, साम्प्रदायिक सामाजिक विद्वेष पर आधारित अपनी पिछली नीतियों का परित्याग कर सकारात्मक कदम उठायेगी ।

■

क्यों रैगिंग शब्द से छूटती है कंपकंपी

रैगिंग का आरंभिक रूप संभवतः महाविद्यालय में प्रवेश करने वाले नए छात्रों के सीनीयर छात्रों से परिचय के रूप में रहा होगा। लेकिन बाद में विकृति इस हद तक पहुंच गई कि छात्र उत्पीड़न से त्रस्त होकर आत्महत्याएं करने लगे, तो कुछ मामलों में यातनाओं का स्तर मौत का कारण बन गया। कॉलेजों के सत्र आरंभ होने जा रहे हैं और इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है युवाओं की और छात्रों का रैगिंग को लेकर क्या रूख रहेगा परिचर्चा के माध्यम से सामने लाये हैं *उमाशंकर मिश्र।*

नीरज / इलाहाबाद

रैगिंग शब्द सुनते ही महाविद्यालय के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की रूह तक कंपकपा जाती है। ऐसे में जब इस शब्द की हकीकत सामने आती है तो उनका हाल कितना बेहाल होता होगा। इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। अपने विद्यार्थी जीवन में इस कटु अनुभव से रू–ब–रू होने वाले लोगों का मन तो उन घटनाओं को याद कर आज भी कड़वाहट से भर जाता है। उन सीनियर्स के खिलाफ आज भी आक्रोश जाग उठता है जिन्होंने बॉस के रूप में उनकी रैगिंग ली थी। इन घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं लगी होती तो वे घटनाएं आज भी समाज के लिए इंजीनियर व डॉक्टर तैयार करने वाले कॉलेज में भयावह रूप में सामने आ रही होती। सुप्रीम कोर्ट के बनाए कानूनों ने इस व्यवस्था को बदला है। साथ ही सीनियर्स पर भी शिकंजा कसा है, जो रैगिंग की पीड़ा से रूबरू होने के बाद भी अपने जूनियर को उसी पीड़ा का बेदर्दी से अहसास कराते थे। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीनीयर छात्रों में जहां एक डर बना है, वहीं कॉलेज प्रशासन भी रैगिंग के मामले पर सक्रिय हुए हैं। महाविद्यालय में रैगिंग की रोकथाम के लिए व्यापक प्रबंध किए जाते हैं। दीवारों पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बारे में जानकारी देने वाले पोस्टर्स लगाकर सीनियर्स को बताया जाता है कि रैगिंग उनके लिए कितनी घातक साबित हो सकती है। इसके अलावा खुद शिक्षक वर्ग भी इस पर नजर रखता है, जो कि एक अच्छी बात कही जा सकती है।

योगेन्द्र मिश्र / प्रतापगढ़,उ.प्र.

हालांकि उच्चतम न्यायालय ने रैगिंग पर रोक लगा दी है, लेकिन अभी यह सिलसिला थम नहीं रहा है, जो कि विडंबनापूर्ण है। रैगिंग सभ्य समाज पर एक कलंक है। इसके आरंभिक दौर की बात करें तो रैगिंग का स्वरूप परिचयात्मक रहा होगा, लेकिन बात में यह वीभत्स होता चला गया। जब हालात छात्रों की मौत तक पहुंच गए तो इस पर कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बावजूद भी गाहे–बगाहे रैगिंग के बहाने छात्र उत्पीड़न की दास्तान सुनने को मिल जाती हैं। रैगिंग के नाम पर छात्रों का उत्पीड़ित करना बर्बर कृत्य है, मानवाधिकार के विरुद्ध है और इस पर लगाम लगाने के लिए सख्ती से कदम उठाने होंगे।

बृजेश पाण्डेय / दिल्ली

यह सही है, और आवश्यक भी है कि वरिष्ट छात्रों व नवागंतुक छात्रों के बीच स्नेह, आदर और मित्रता का संबंध हो और यह भी ठीक ही है कि वरिष्ठ छात्र यह अपेक्षा करें कि कनिष्ठ छात्र उन्हें सम्मानयुक्त मित्रता की दृष्टि से देखें। मैं यह भी मानता हूँ कि इस के लिये रैगिंग (शाब्दिक अर्थ में नहीं) तो अपरिहार्य है, पर इस रूप में नहीं जैसे कि आम तौर पर पाया जाता है। यदि रैगिंग को स्वस्थ, मनोरंजक, मज़ाकिया व चुटकी

के रूप में अपनाया जाय तो संभवतः यह संस्कार एक बेहतर आनंददायी व अपने वास्तविक प्रयोजन में अधिक सफल हो। इसमें सीमित मात्रा में मज़ाक, कुछ हद तक मौज, कुछ सूचनात्मकता, कुछ सामान्य व विशिष्ट ज्ञान आदि सही–सही अनुपात में समाहित किये जाएं तो यह प्रक्रिया रचनात्मक भी हो सकती है। यह विशेष ध्यान रहे कि मज़ाक अथवा मानसिक चुटकियों की मात्रा व सीमा का उल्लंघन कदापि न हो और उचित समय पर इसे सुखद माहौल में ही समाप्त किया जाय।

अमित कुमार / दिल्ली

रैगिंग का विकृत होता स्वरूप और बदले की भावना वास्तव में गंभीर है, मात्र अनुशासनात्मक कार्यवाही और कानून के भय से इस परंपरा को बदला नहीं जा सकता। शायद

वरिष्ठ छात्रों को यह समझाकर कि यदि इस परंपरा को वे सुधारने में व उत्पीड़न को समाप्त करने में सहायक हों, व स्वस्थ और हल्के–फुलके रूप से (फुरसतिया ब्रॉड) मौज / चुटकी ले कर परिचय व साक्षात्कार की रस्म पूरी करें तो सभी के लिये भला होगा और नवागंतुक (अनुज) उन्हें अधिक सम्मान मिश्रित स्नेह देंगे तो कदाचित उत्पीड़न के रिवाज़ कुछ कम हों। हमारे मनोचिकित्सक भी सत्रारंभ के पहले यदि अपने लेख व सामूहिक गो ठी व ऐसे प्रयासों से वरि ठ छात्रों व संस्थान प्रबंधन से मिलकर, उन्हें सलाह दे कर कदाचित इस प्रक्रिया के हानिरहित व धनात्मक पहलुओं को सामने लाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। ■

ABVP Demands Nationwide Debate on Yashpal Committee Recommendations

ABVP welcomes the initiative taken by union HRD minister Shri. Kapil Sibal to keep on hold the approvals of new deemed universities and for conducting strict review of existing deemed-universities for their performance, admissions and fee structure. ABVP is of the opinion that deemed-universities are now the back door entries for commercialization of education and should be reviewed. ABVP is of the strong opinion that the Yashpal Committee Report on higher education, submitted to the center should be made public and nationwide debate must be initiated immediately on various recommendations of it ,as they have long range consequences in education field. ABVP recollects the discussions carried out by the then P.M. late shri. Rajeev Gandhi before introducing New Education Policy in 1986.

Concept of setting up of National Commission for Higher Education and research (NCHER), must be debated by concerned stake holders, about its nature, functioning, scope and responsibilities. The idea of such commission originated from Kothari Commission Report in 1968. ABVP has been supporting the concept of autonomous National Commission for the last three decades. The present proposed structure of NCHER is over centralized which may lead to functional problems like over bureaucratization and red-tapism in higher education.

ABVP has strong reservations about the HRD ministers proposal to keep 10th standard examination optional, grades in place of marks for 9th and 10th standard and centralized school board for the country. Though, optional 10th standard examination is the proposal only for CBSE today, but there is every possibility of extending the same to state school boards also after some period. So there is a need for a standard state wide examination which will function as the basic qualifying marks for admissions in 11th standard. As the present system seems to be well established and there is a general acceptability for the same, ABVP feels the present system should not be disturbed in the name of radical reforms.

भारत सरकार की 100 दिवसीय शैक्षिक कार्य योजना

— डा.कैलाश शर्म —

भारतीय समाज के सदियों की पराधीनता के बावजूद समाज में चैतन्यता बनी रही । इसका प्रमुख कारण यहां की शिक्षा व्यवस्था ही थी । परन्तु दूरगामी परिणामों को ध्यान में लेकर 19वी सदी के पूर्वान्ह में भारत के शिक्षा तंत्र को दूषित करने के प्रयास प्रारम्भ हो गये। स्वतंत्र भारत में उनको रोका नही गया अपितु अंग्रेज की अनिष्टकारी शैक्षिक नीतियों को न केवल निर्बाध रूप से चलाये रखा बल्कि कालान्तर में और अधिक विकृत स्वरूप प्रदान कर दिया । यहां तक कि गत एक दशक में अनेक अनर्थकारी प्रयोग प्रारम्भ हो गये। जब अमेरिका की अगुवाई में तथाकथित विकसित देश शिक्षा जैसे पवित्र सामाजिक कार्य को भी विश्व व्यापार संगठन के सेवा क्षेत्र में लाकर उसके माध्यम से व्यापार करने की योजना कार्यरूप में परिणित करने में लगे थे और वैसी ही उपेक्षा भारत से भी कर रहे थे। हालांकि दुनिया के तमाम लोगों के विरोधस्वरूप उनकी वह योजना अभी अधिकारिक रूप से लागू नही हो पायी है। परन्तु भारत के शासनकर्ताओं ने भारत में शिक्षा का बाजार बनाने में कोई कसर बाकी नही रखी है। दूसरी ओर अपने राजनैतिक मंतव्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा का वामपंथीकरण और साम्प्रदायीकरण भी भरपूर हुआ है और हो रहा है। इसी पार्श्वभूमि में केन्द्र में हाल ही में बनी नई सरकार के मानव संसाधन मंत्री ने एक 100 दिवसीय कार्ययोजना का भी ऐलान किया है ।

इन योजनाओं में दो विषयों का देशभर में स्वागत हुआ है । एक प्रो. यशपाल समिति के अंतरिम निष्कर्षों पर सैद्धान्तिक सहमति और दूसरा मानित विश्वविद्यालयों की हाल में दी गई मान्यता पर रोक । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तत्काल अपने वक्तव्य के माध्यम से इन घोषणाओं का स्वागत किया । साथ ही इन अनुशंसाओं पर देश का विचार जानने का भी आह्वान किया । क्योंकि विस्तृत अनुशंसायें आना अभी बाकी है ।

प्रो. यशपाल समिति ने एक स्वायत्त शिक्षा आयोग गठित करने की अनुशंसा की है । लेकिन इस प्रकार के आयोग की संरचना, कार्यक्षेत्र और कार्याधिकार क्या होंगे? वर्तमान में कार्यरत अनेक उच्च शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं का क्या होगा? अभाविप ने भी स्वायत्त शिक्षापीठ की स्थापना की बात पिछले कई वर्षों से लगातार कही है जिसके अनुसार प्राथमिक से लेकर उच्चतम शिक्षा की योजना, चिंतन, पाठ्यचर्या, संभाल और गुणवत्ता सम्बन्धी शिक्षा के सभी पक्षों पर यह आयोग विचार करे । निर्वाचन आयोग या न्यायालय के समकक्ष इस आयोग की क्रियाविधि हो । यह पूर्णतः स्वायत्त रहे आदि । कई सुझाव अभाविप ने सरकार के सामने रखे हैं । इनमें से केवल कुछ प्रश्नों के बारे में ही यशपाल का संक्षेप में सुझाव है। लेकिन इस प्रकार के व्यापक असर करने वाले निर्णय को देश का विचार व्यापक रूप से जानकर लागू करवाने की पहल की जानी चाहिए ।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने नामित विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उठी अनेक आशंकाओं और भ्रष्टाचार के प्रश्नों के समाधान के लिए नये नामित विश्वविद्यालयों को अनुमति न देने और हाल ही में दी गई ऐसी मान्यताप्राप्त संस्थाओं के बारे में जांच करवाने की घोषणा की है । यह एक सकारात्मक कदम है । जिस प्रकार श्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल में अनेक संस्थाओं की जांच की जाच प्रकरण किये बगैर और नामित विश्वविद्यालय सम्बन्धी मूल नियमों की अनदेखी करते हुए कई निम्न स्तर की संस्थाओं को भी मानित विश्वविद्यालय की मान्यताए प्रदान की गई थी। उनकी व्यापक निन्दा समाज में हुई थी । केवल शिक्षा में

व्यापार को बढ़ाने वाला यह कदम था । शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक निम्न स्तर पर ले जाने वाले इस प्रकार के निर्णय की भर्त्सना स्वाभविक रूप से हुई थी । हालांकि इस दृष्टि से ईमानदारीपूर्वक बिना किसी दबाव और हस्तक्षेप के श्रेष्ठ संस्थानों को प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए । परन्तु नियमों का दुरूपयोग रोकने के लिए आवश्यक विधायी प्रतिबन्धों की भी आवश्यकता रहती है ।

एक स्वायत्त, आत्मनिर्भर एजेन्सी (जो उच्च शिक्षा के मूल्यांकन और स्तर का निर्धारण करे) की स्थापना की बात भी 100 दिवसीय कार्ययोजना में कही गई है । परन्तु इस प्रकार की पूर्व में गठित संस्थाओं का क्या होगा? इन संस्थाओं ने अपना कार्य नहीं किया तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? अरबों रूपये ऐसी संस्थाओं के द्वारा व्यय होने के बाद बिना किसी की जिम्मेदारी तय किये नई–नई संस्थाऐं खोलने का उद्देश्य क्या? क्या इस प्रकार अनुत्पादक जवाबदेही रहित नयी–नयी संस्थायें निरूत्तर रूप से खड़ी करना और चलाये रखना आवश्यक है । ऐसे कई सम्बन्धित प्रश्नों के समाधान निकालकर ही आगे बढ़ना चाहिए ।

परन्तु केन्द्र सरकार कुछ अधिक हड़बड़ी में है शायद । जो विषय व्यापक विचार–विमर्श चाहते हैं उन विषयों को भी आनन–फानन में तय करना कहां तक उचित है । 10वीं कक्षा की परीक्षा स्थापित केन्द्र और राज्यों के बोर्ड करवाते हैं । इनकी एक प्रकार की अच्छी प्रसिद्धि भी है । मैट्रिक के प्रमाण–पत्र की मान्यता कई कार्यों में रहती है । जन्मतिथि प्रमाण पत्र आदि के लिए तो यह एक महत्वपूर्ण प्रपत्र माना जाता है ।

मैट्रिक परीक्षा पास करना अपने आप में एक सम्मानजनक अवस्था का परिचायक समाज में बन चुका है । छात्र आगे की पढ़ाई किसी विशेष धारा की तरफ करना– इसका निर्धारण 10वीं के अंकों के आधार पर होता है । फिर इस परीक्षा को रद्द करना या ऐच्छिक बनाना कहां तक ठीक है । एक कुतर्क दिया गया है कि 10वीं की परीक्षा से बालक तनावग्रस्त हो जाते हैं । कुछ गिने–चुने उदाहरण तनाव के नाम पर सामने आये होंगे। तो क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस बात की गारन्टी देता है कि 10वीं की परीक्षा समाप्त होने के बाद कोई बालक देश में तनावग्रस्त नही होगा । बालक तनावग्रस्त होते नहीं है किया जाता है माता–पिता और शिक्षकों द्वारा । माता–पिता अपनी अपूर्ण लालसाओं को / कामनाओं को अपने बच्चों से पूर्ण करवाने के लिए उन्हें किताबी कीड़ा बनाना चाहते हैं । पाश्चात्य जीवन–शैली अपनाकर जीवन में उनके अनचाहे प्रश्न खड़े करवाकर बच्चों को तनावग्रस्त बनाते हैं । सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है । जो हैं उनको अशैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाता है । क्यूं विद्यालयों में कम वेतन पर अयोग्य या कम योग्यता वाले लोगों से काम चलाया जाता है । अधिकांश विद्यालयों में कक्षा कार्य न्यूनतम और गृह कार्य अधिकतम का वातावरण है । जिसे पूर्ण करवाने के दबाव और कैरियर की चिंता में ट्यूशन पर जाना सामान्य बात हो गयी है । बच्चे परीक्षाओं से ज्यादा तनावग्रस्त कम और अन्य कारणों से तनावग्रस्त ज्यादा हो रहे हैं । इस आधार पर 10वीं जैसे प्रसिद्ध सार्वजनिक परीक्षा के ऊपर प्रश्न लगाया न केवल अव्यावहारिक बल्कि अदूरदर्शितापूर्ण कदम है ।

उच्च शिक्षा के निधि निवेश के नाम पर गत एक दशक में शिक्षा में बाजारवाद और व्यापारीकरण का वातावरण बन गया है । इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की योजना 100 दिवसीय कार्ययोजना की घोषणाओं में भी परिलक्षित होती है । विद्यालयों में गुणवत्ता लाने के लिए एक हास्यास्पद प्रयोग सुझाया गया है । जिसके अनुसार सरकारी विद्यालयों के भवन को निजी लोग किराये पर लम्बे और समकामी और अपने बालकों को गुणवत्ता की शिक्षा देवें । शैक्षणिक संस्थानों के भवनों को किराये पर देकर या बेचकर वित्त व्यवस्था खड़ी करना सरकार का मूर्खतापूर्ण कदम होगा । देश की शिक्षा को और अधिक बर्बाद करने से बाज आयें देश के शासनकर्ता । और देश को विश्वास दिलायें कि कोई तुगलकी निर्णय शिक्षा–क्षेत्र में नही करेंगे । यदि सुधारात्मक कुछ कदम उठाना चाहते हैं तो शिक्षा में सरकारी निवेश को बढ़ायें । योग्य शिक्षकों की नियमित नियुक्ति तत्काल करें और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन – अध्यापन का वातावरण विद्यालयों में बनवायें । ■

Jammu & Kashmir

Seminar on Technical Education, in Jammu

Akhil Bhartiya Vidyarathi Parishad Jammu Kashmir organised one day seminar on Technical Education on the 150th Birth anniversary of Great Indian Scientist Sh.Jagdish Chander Bose in Jammu University .The Seminar was Divided into 3 session .First was inagural session (topic. need and relevence of tech.education) in which Divisional Commisioner Dr.Pawan Kotwal was cheif guest D.I.G of police mr.A.Q.Mahnas was the guest of honour . Retd.Maj.Gen.S.K.Sharma was the main Speaker.

Sh.Bihari Lal Sharma, North Zone Organising Secy.ABVP Presided over the function. Dr.Rakesh Sharma welcomed the delegates and Suresh Ajay Magotra, State Secy.ABVP delevered the vote of thanks. Topic of the 2nd session was Science -Indian pride and Contribution. Prof.Narinder Singh (National Excutive member ABVP) chaired the session and Sh.Suresh Ajay Magotra was the main speaker. 3rd Session was on Technical Education Vision and Scope . Dr Varinder Kaoundal, State Vice Prisident chaired the session while Prof. K.C.Gupta, Ex. Prof B.I.T..S Pillani addressed the delegates.165 delegates (20 Research Scholars , 20 teachers, 52 girls and 73 boys) from 5 techinical institute of state participated in the seminar.

Eastern UP

ABVP submitted five point demand to VC

ABVP held a demonstration in front of administrative block of DDU Gorakhpur University and submitted five-point-demand to the Vice Chancellor. They threatened to launch state-wide agitation if their demands are not accepted by the university authorities.

The demands include declaration of the examination results of the academic session 2008-09 at the earliest and the closure of admission in PG classes until all the results are declared. To cope with the demands for more admission at the undergraduate level, there should be an increase in seats to 25 per cent in every subject at undergraduate level as per the order of the state government.

Rooms should be allotted to the students in the hostels who have already taken admission and students should not be punished due to the faults committed by the management of affiliated colleges.

They alleged that till date only 20 per cent results of the undergraduate final year have been declared and last date for submission of admission forms for postgraduate courses in the university has been closed. Admission dates for PG courses have been declared. "What would be the fate of those students who are aspiring to study in the university and their results are yet not declared," they questioned. They threatened to start agitation if their demands are not met and the process of admission, in PG courses, not suspended till the declaration of all university results

Kerala

Defer C&S pattern, demands ABVP

ABVP Kerala state unit has demanded that the choice-based Credit and Semester Pattern for undergraduate courses, which is in various stages of implementation in the Mahatma Gandhi, Kannur and Calicut Universities, should be put

on hold and piloted in a foolproof manner, preferably only from the next academic year.

ABVP has also demanded the scrapping of the State Higher Education Council headed by Dr K N Panicker alleging that the body was consistently interfering in the autonomy of Universities in the State.

Presenting the deliberations and conclusions of the ongoing ABVP state sibiram , state president S Manu, secretary G M Mahesh, vicepresident P P Rajesh and Kottayam district convener Lal Krishnan told a news conference here that that Higher Education Council was imposing its pre-conceived diktats upon the Universities, by making the Academic councils and Board of Studies non-entities and voiceless.

The Council has prepared the list of subjects as well as the curriculum for credit and semester pattern of undergraduate courses beforehand and goaded the varsities to issue the same to affiliated colleges, they charged.

Karnataka

ABVP seeks appology from KPCC Boss

ABVP Karnataka Unit announced that it would file a defamation case against Congress Working President D K Shivakumar.

Shivakumar had recently held ABVP volunteers responsible of leaking the BCom examination paper of Bangalore University.

Speaking to the press, ABVP State Joint Secretary, Tammesh Gowda terming Shivakumar's allegations baseless, said: "We have decided to file a defamation case against him and legal notice has been served for the same." ABVP volunteers, staged a protest near Anand Rao flyover, demanding that the State government conduct a probe against the National Student Unions' of India and alleged that the organisation was collaborating with a private TV channel for unethical sting operations.

Thammesh said that after the sting operation that allegedly exposed an ABVP leader in the paper leak scandal; the accused, instead of being taken to the police station was taken to the Congress office. He further demanded the arrest of the lecturer accused in the paper leak scandal.

Mahakoshal

ABVP intensifies protest against attacks on Indian students

Peeved at the attacks on Indian students in Australia, the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) intensified its protested and ransacked the Centre of Australian Unified Pathway Programme (AUPP) at Mahanada in Jabalpur on June 13. Police used mild cane charge to disperse the activists and arrested eight of them under section 151. ABVP state secretary Abhilash Pandey said the police rained lathis on the students protesting peacefully, adding that ten protesters were injured in the police's act. He said, the incident took place when after getting enrolled at AUPP the Indian students were going to Australia where they are still facing violent racial attacks.

The ABVP activists on June 14 targetted another institute, Anand Institute of International Studies, which facilitates admission to Australian universities to express anguish over racial attacks on Indian students. "The police baton-charged us after chasing us down. Our friends were also injured," said Shri Durgesh Kumar, one ABVP activist. The ABVP activists held a protest march in Bengaluru and Madurai also raising their voice against the recent attacks on Indian students. About 300 ABVP activists took out a protest march at Anand Rao Circle in Bengaluru, shouting slogans, denouncing the attacks and demanding justice.

Protest against attack on Indian students in Australia- Karnataka

Human Chain to protest against the collection of development fees by DVS polytechnic - Shimoga, Karnataka

छात्र शक्ति
ABVP
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
ज्ञान • शील • एकता
1949-2009
60
एक आन्दोलन देश के लिए